सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 230 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, बुधवार 03 जून 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय नारायणपुर को पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026

रायपुर। पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन, जैव विविधता संरक्षण, जैविक कृषि, वृक्षारोपण, नशामुक्ति जागरूकता एवं जनसहभागिता आधारित पर्यावरणीय अभियानों में उत्कृष्ट एवं नवाचारपूर्ण कार्यों के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधीनस्थ लिंगो मुदियाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, नारायणपुर को 'पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान नमामि गंगे परियोजना तथा भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में प्रदान किया गया। देशभर से प्राप्त 100 से अधिक नामांकनों में से केवल 9 संस्थाओं को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुना गया, जिनमें एक विश्वविद्यालय, पांच विद्यालय एवं तीन महाविद्यालय शामिल थे।

पटना में खान सर की कोचिंग पर हमला, मारपीट

पटना। मंगलवार रात खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज पर हमला हुआ। हमले का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग गार्ड को पीटते दिख रहे हैं। इस दौरान ईंट-पत्थर भी चलाए गए। पोस्टर भी फाड़ दिए। पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद समेत उनके दो सहयोगी अभिषेक और गौरव को गिरफ्तार किया है। तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है।

बंगाल में टीएमसी नेता घूस के पैसे हितग्राही को लौटा रहे

कोलकाता। पश्चिम बंगाल से तृणमूल नेताओं के लोगों को पैसे बांटने के वीडियो वायरल हैं। दावा है कि यह वो कट मनी यानी कमीशन है जो उन लोकल नेताओं ने स्थानीय लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बदले में लिया था। अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। राज्य में भाजपा की सरकार है। इसलिए ये नेता डर से लोगों को उनसे लिया पैसा लौटा रहे हैं। भाजपा आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने भी अपने-अकाउंट पर 2 वीडियो शेयर किया।

11 राज्यों में आंधी बारिश, आगरा में सड़क धंसी

नई दिल्ली। देशभर में आंधी-बारिश से पारा 40 डिग्री के नीचे आ गया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात में बारिश हुई। यूपी के आगरा में करीब एक घंटे तक तेज बारिश से सड़कें और फुटपाथ धंस गए। इसमें ट्रैक्टर-ट्रॉली, कारें और ट्रक पलट गए। एमपी के सिंगरौली में बिजली गिरने से किशोर की और नीमच में जर्जर मकान की छत गिरने से मां-बेटे की मौत हो गई। जम्मू-कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़ और पुंछ जिलों में बादल फटे। इससे सड़कें जाम हो गईं, रिहायशी इलाके पानी में डूब गए।

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता मुक्त समाज का 91 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर छत्तीसगढ़ बना नम्बर-1

हर्षित अग्रवाल

रायपुर। अंधत्व एक अभिशाप है। हालांकि सही समय पर हस्तक्षेप कर बड़ी संख्या में लोगों की दृष्टि को बचाया या लौटाया जा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। छत्तीसगढ़ ने 2025-26 के लिए निर्धारित लक्ष्य का 91 फीसद हासिल कर देश भर में श्रेष्ठ निष्पादन करने वाले राज्य का तमगा हासिल कर लिया है। इस अवधि में छत्तीसगढ़ में 1 लाख 63 हजार 641 से अधिक मोतियाबिंद ऑपरेशन पूरे किए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा शासकीय संस्थानों, गैर-शासकीय संगठनों और निजी अस्पतालों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर इस लक्ष्य को हासिल किया। इसका परिणाम यह है कि दूरस्थ क्षेत्रों तक भी नेत्र उपचार सेवाएं पहुँच रही हैं और आर्थिक रूप

से कमजोर मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है।

राज्य की उपलब्धि में शासकीय एवं अनुबंधित अस्पतालों की भागीदारी 51 प्रतिशत रही, जबकि निजी क्षेत्र ने 49 प्रतिशत योगदान देकर इस स्वास्थ्य अभियान को गति दी। यह साझेदारी मॉडल न केवल उपचार की पहुँच बढ़ा रहा है, बल्कि समयबद्ध और व्यवस्थित नेत्र चिकित्सा प्रबंधन का भी उदाहरण बन रहा है।

कोविड काल का दंश

कोविड काल में मोतियाबिंद के लंबित मामलों में वृद्धि हुई थी। लेकिन अब स्थिति बेहतर है। भारत सरकार की राष्ट्रीय नेत्र ज्योति योजना के तहत घर-घर सर्वे कर चिन्हित मरीजों का उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जिलों को कैटरेक्ट ब्लाइंडनेस बैकलॉग फ्री स्टेटस दिलाने की दिशा में ठोस प्रगति हो रही है।

भारतीय मौसम विज्ञान के बाद अब विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दी चेतावनी

पूरी दुनिया पर मंडराने लगा सूखे का खतरा, भारत में आईओडी और एमजेओ से बच सकता है मानसून

एजेंसियां

नई दिल्ली। भारत समेत पूरी दुनिया पर सूखे का खतरा मंडरा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के बाद विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने भी वैश्विक जलवायु को लेकर चेतावनी जारी की है। मौसम एजेंसी के मुताबिक तेजी से गर्म हो रहे प्रशांत महासागर के कारण जून से अगस्त के बीच अल नीनो की आशंका 80 प्रतिशत है। नवंबर तक इसके 90 प्रतिशत या उससे भी अधिक होने की संभावना है। पर भारत में एक्टिव दो सिस्टम इस खतरे को कम कर थोड़ी राहत दे सकते हैं।

भारत में इंडियन ओशन डायपोल (आईओडी) और मैडेन-जूलियन ऑस्सिलेशन (एमजेओ) से मानसून बच सकता है। ये बादलों और हवाओं का एक ऐसा वैश्विक सिस्टम है तो मूमध्य रेखा पर घूमता रहता है। जब यह भारत के ऊपर से गुजरता है, तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश के स्पेल (दौर) लेकर आता है।

मौसम विभाग के मुताबिक मानसून में सामान्य से कम बारिश की संभावना है। दक्षिण-पश्चिम मानसून अभी लेट है। इसके 4 जून को केरलम पहुंच सकता है। आमतौर पर मानसून 1 जून के आसपास केरलम पहुंचता है।

डब्ल्यूएमओ के मुताबिक, अल नीनो आगे चलकर और मजबूत हो सकता है। इससे भारत समेत दुनियाभर में सूखा, बाढ़, समुद्री-स्थलीय हीटवेव और मौसम के खतरनाक रूप देखने को मिल सकते हैं।

समुद्र 6 डिग्री ज्यादा गर्म : डब्ल्यूएमओ के मुताबिक, प्रशांत महासागर की सतह के नीचे का पानी सामान्य से 6 डिग्री तक ज्यादा गर्म मिला है। समुद्र में जमा यही अतिरिक्त ऊष्मा सतह को गर्म कर रही है, जिससे अलनीनो को रफ्तार मिल रही है।

कृषि मंत्रालय का अलर्ट : कृषि मंत्रालय ने कहा है कि कम मानसून और अल नीनो की आशंका को देखते हुए जिलास्तर पर प्लान लागू करें। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों तक जल्दी जानकारी पहुंचाने के लिए डिजिटल और कॉल सेंटर सेवाओं को मजबूत करें।

भारत में दो सिस्टम सक्रिय : भारत में इंडियन ओशन डायपोल (हिंद महासागर का अल नीनो) सक्रिय है। इसका फेज पॉजिटिव होने पर तो यह अल नीनो के प्रभाव को पूरी तरह खत्म कर भारत में अच्छी बारिश करा सकता है। वहीं मैडेन-जूलियन ऑस्सिलेशन जब यह भारत के ऊपर से गुजरता है, तो कमजोर मानसून में भी भारी बारिश के स्पेल (दौर) लेकर आता है।

सीजीपीएससी भर्ती घोटाला : परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के घर रेड

- रिटायर्ड आईएएस और राज्यपाल के पूर्व सचिव के ठिकानों पर छापे

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग-भिलाई। सीजीपीएससी भर्ती परीक्षा घोटाले में रायपुर, दुर्ग-भिलाई में छापेमारी की गई है। परीक्षा नियंत्रक आरती वासनिक के रायपुर स्थित घर में कार्रवाई चल रही है। वहीं रिटायर्ड आईएएस जेके ध्रुव के भिलाई सेक्टर-10 स्थित घर पर सुबह 6 बजे से जांच जारी है।

बता दें कि जेके ध्रुव सीजी-पीएससी भर्ती घोटाले में भी आरोपी हैं और फिलहाल जेल में हैं। इस कार्रवाई को भारतमाला घोटाला मामले में उनके कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।

वहीं राज्यपाल के पूर्व सचिव अमृत खलखो के भिलाई तालपुरी स्थित निवास पर भी जांच चल रही है। बता दें कि उनकी बेटी नेहा का 13वीं रैंक और बेटे निखिल का 17वीं रैंक के साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयन हुआ था।

क्या है मामला?

यह मामला 2020 से 2022 के बीच हुई भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़ा है। आरोप है कि आयोग की परीक्षाओं और इंटरव्यू में पारदर्शिता को दरकिनार कर राजनीतिक और प्रशासनिक रसूख वाले परिवारों के उम्मीदवारों को उच्च पदों पर चयनित किया गया। इस दौरान योग्य अभ्यर्थियों की अनदेखी कर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी और अन्य राजपत्रित पदों पर अपने नजदीकी लोगों को पद दिलवाने का खेल हुआ।

मालवीय नगर के लेमनग्रीन रेस्तरां में भीषण आग, 21 लोगों की मौत

नई दिल्ली (ए.)। मालवीय नगर इलाके में लेमन ग्रीन नाम के एक रेस्टोरेंट में बुधवार को भीषण आग लग गई। हादसे में 21 लोगों की जलकर मौत हो गई है। इनमें कई विदेशी हैं। अग्निशमन सेवा को सुबह 09:45 पर सूचना मिली जिसके बाद बेसमेंट समेत पूरी इमारत से करीब 37 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इनमें से कई गंभीर रूप से घायल हैं। समाचार लिखे जाने तक इमारत में फंसे अन्य लोगों को ढूंढने और रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है।

डीडीएमए साउथ डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया, सूचना मिलते ही उन्होंने अपने सेल को सक्रिय किया और सभी बलों को रवाना किया गया। इमारत के नीचे कोई होटल चलाया जा रहा था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि ऐसे हादसे दोबारा न हों इसलिए सख्त कार्रवाई करनी आवश्यक है. यह होटल किसी और लाइसेंस की आड़ पर चलाया जा रहा था। समय पर बीएसईएस ने बिजली की सप्लाई बंद कर दी वरना हादसा और भयंकर हो सकता था।

एसडीएम ने बताया कि आग फैलने के बाद बाहर आने के रास्ते नहीं बचे थे। स्थानीय लोगों ने बिल्डिंग के आगे जमीन पर गद्दे लगा दिए थे। इसके बाद लोग बालकनी और खिड़की आदि से नीचे कूदे थे। एमसीडी से जानकारी मांगी गई है कि ऐसे कितने होटल और रेस्टोरेंट को रिहायशी इलाके में संचालन का लाइसेंस दिया गया है। सभी की एक रूटीन जांच की जाएगी।

मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय ने बताया, बहुत ही दुखद घटना है। सुबह 9.00 बजे सूचना मिलते ही उन्होंने तत्काल पूरे सिस्टम को सक्रिय किया और स्वयं भी मौके पर पहुंचे।

रायपुर में सफाई ठेकेदारों की हड़ताल, 4 महीने से भुगतान नहीं

रायपुर। नगर निगम की सफाई व्यवस्था को फिर बड़ा झटका लगा है। भुगतान नहीं मिलने से नाराज सफाई ठेकेदारों ने बुधवार से काम बंद कर दिया है। इसके चलते निगम के सभी 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सफाई ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से भुगतान लंबित हैं। इसी मांग को लेकर 2 दिन पहले उन्होंने नगर निगम आयुक्त और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को ज्ञापन भी सौंपा था।

500 तहसीलदार हड़ताल पर, भटक रहे लोग

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर/सरगुजा। छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा तहसीलदार आज हड़ताल पर हैं। राजस्व कामकाज बंद कर अधिकारियों ने सीतापुर से भाजपा विधायक रामकुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग की है। आरोप है कि एमएलए ने सरगुजा जिले के नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई की थी।

इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज प्रदेशभर के तहसीलदार राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। हड़ताल के कारण राज्य की अधिकांश तहसीलों में कामकाज पूरी तरह ठप है। लोग राजस्व कामकाज के लिए भटकते दिखाई दिए। इससे पहले 30 मई को कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी संघ ने हड़ताल की थी। तब विधायक ने खुद गिरफ्तारी देने की बात कही थी। हालांकि अब तक कार्रवाई नहीं होने पर आज फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल उठाते हुए सरकार पर विधायक को बचाने का आरोप लगाया है।

क्या है मामला : विधायक टोप्पो का आरोप है कि, नायब तहसील-दार तुषार ने उनकी चचेरी बहन से अभद्रता की थी। वहीं तुषार का आरोप है कि विधायक और उनके समर्थकों ने उनकी पिटाई की थी।

पीएम स्वनिधि के 6 साल पूर्ण, 30 जून तक चलेगा विशेष अभियान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। फुटपाथ पर व्यापार करने वाले और छोटे व्यापारियों के लिए बनाई गई प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (स्वनिधि) योजना के छह साल पूरे हो गए हैं। योजना से अब उन फुटकर व्यापारियों को भी जोड़ा जाएगा जो इसके लाभ से अब तक वंचित रहे हैं। इसके लिए निकाय तथा जिला स्तर पर 30 जून तक लोक कल्याण मेलों का आयोजन किया जाएगा।

राज्य शासन ने सभी नगरीय निकायों को परिपत्र जारी कर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं। नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को स्ट्रीट वेंडर्स, शहरी गरीबों एवं असंगठित श्रमिकों को वित्तीय समावेशन, डिजिटल सशक्तीकरण और सामाजिक सुरक्षा के लाभों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव शंगीता आर. ने बताया कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में लोक कल्याण मेले लगाए जाएंगे, जबकि जिला मुख्यालयों में स्वनिधि महोत्सव आयोजित किए जाएंगे।बैंकों के प्रतिनिधि छोटे व्यापारियों को ऋण स्वीकृति, वितरण, यूपीआई पंजीयन, क्यू-आर कोड सुविधा और डिजिटल भुगतान संबंधी सेवाएं तत्काल उपलब्ध कराएंगे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों विशेष रूप से महिला स्ट्रीट वेंडर्स और दिव्यांग व्यापारियों को मंच पर सम्मानित किया जाएगा।

बिखरने लगा टीएमसी का कुनबा, बागी विधायक संदीपन ने किया 59 विधायकों के समर्थन का दावा

कोलकाता (ए.)। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) दो गुटों में बंट सकती है। टीएमसी से निकाले गए 2 विधायक संदीपन साहा और ऋतब्रत बनर्जी बुधवार सुबह 11 बजे विधानसभा पहुंचे। वे स्पीकर से मिलकर 59 विधायकों के समर्थन का दावा पेश कर सकते हैं।

बागी विधायक स्पीकर के सामने तीन मुद्दे उठाएंगे। पहला- वे ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा- विपक्ष के नेता ऋतब्रत होंगे, न कि शोभनदेव। तीसरा- उनके पास दो-तिहाई बहुमत है, इसलिए चुनाव चिह्न उनका होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुट को मान्यता के लिए दो-तिहाई यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इससे कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुट को मान्यता नहीं देंगे।

सोमवार को संदीपन और ऋतब्रत ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इसमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए थे।

टीएमसी टूट की 3 संभावनाएं

दो तिहाई विधायक भाजपा में शामिल हों। टीएमसी के कुल 80 विधायकों में से दो तिहाई (54 विधायक) भाजपा में शामिल होने का फैसला लें। ऐसे में दलबदल कानून नहीं लगेगा। हालांकि भाजपा ने इनकार कर दिया है।

टीएमसी खुद 2 गुटों में बंट जाए। एक ग्रुप पार्टी से अलग होकर असली टीएमसी का दावा करे। इसके लिए भी 54 विधायकों के समर्थन की जरूरत होगा। अगर ऐसा होता है तो बड़े गुट के दावे पर चुनाव आयोग फैसला लेगा। मामला कोर्ट भी जा सकता है। हालांकि इसके लिए दो-तिहाई यानी 28 में से 19 लोकसभा सांसदों की भी जरूरत भी होगी।

किसी पार्टी के बागी नेताओं के लिए सिर्फ विधानसभा संख्या ही निर्णायक नहीं होती। शिवसेना और एनसीपी के मामलों में निर्वाचन आयोग ने केवल विधायक नहीं देखे थे, बल्कि यह भी देखा था कि कितने सांसद किसके साथ हैं, पार्टी संगठन किसके साथ है, अधिकृत पदाधिकारी किसके साथ हैं।

तीसरा: नया गुट अलग होकर अपनी नई पार्टी बना सकता है।

संपादकीय

नशे पर शिकंजा

जम्मू-कश्मीर में सामूहिक प्रयास मददगार

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गठजोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलू यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते-ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सही मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है।

> “ पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वर्षों से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्तर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सौ दिवसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं।

वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की समाज में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियां व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे की डोज जुटाने के लिये कुछ छात्र व युवा अपराध की राहों में फिसल जाते हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि नियमित रूप से नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी करके तुरंत सजा दी जाए। वहीं दूसरी ओर नशे की खरीद-फरोख्त में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, पासपोर्ट निरस्त करने से भी जहरीले कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों में, जहां सीमा पार से नशे की तस्करी आतंकवाद को जिंदा रखने के लिये की जा रही है, वहां अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत है। नशा तस्करों की गिरफ्तारी के तुरंत बाद सजा देना, इस अभियान में मददगार साबित होगा।

भारतीय भूमि अतिक्रमण मुद्दे पर घिरे बालेन्द्र

पुष्परंजन

अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी क़ब्ज़ा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है।

गत 27 मार्च को पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक बार भी संघीय संसद को संबोधित नहीं किया था यहां तक कि अनिवार्य साप्ताहिक प्रश्न-उत्तर सत्रों के दौरान भी नहीं। उनकी चुप्पी तोड़ने और विधायिका के प्रति जवाबदेही दिखाने का दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा था। और फिर रविवार को जब बालेन्द्र शाह संसद में बोले, सभी सन्नाटे में आ चुके थे। उन्होंने अपने आलोचकों को शांत करने के बजाय, मानो डंक मारने वाली मधुमक्खियों का एक झुंड ही छोड़ दिया। जिसे अंग्रेजी में 'पैंडोरा बॉक्स खोलना' कहते हैं।

संसद में दो अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए, शाह ने सबसे पहले कहा कि कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ प्रयास जारी हैं। लेकिन, फिर उन्होंने यह भी जोड़ा कि न केवल भारत ने नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की ज़मीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि भारत के साथ मौजूदा सीमा विवादों में से कई की जड़ें 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ हुई सुगौली संधि में हैं, इसलिए उनकी सरकार भारत-नेपाल सीमा चर्चाओं में ब्रिटिश पक्ष को शामिल करने की कोशिश कर रही है।

काठमांडू पोस्ट जैसा अखबार भी इस बयान से हैरान था। अगले दिन के सम्पादकीय में अखबार लिखता है— 'सीमा विशेषज्ञों के साथ-साथ उन वरिष्ठ पूर्व सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है, ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसमें भारत ने कभी 'नेपाली अतिक्रमण' का मुद्दा उठाया हो। इसलिए, प्रधानमंत्री का यह बयान भविष्य की सीमा वार्ता में भारत के पक्ष को मज़बूत करता है।'

कोई राष्ट्रीय अख़बार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करे, तो यह उभयपक्षीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। भारत से यदि भूमि विवाद नहीं होता, तो 'बाउंडरी वर्किंग ग्रूप' का गठन क्यों किया गया. संयुक्त तकनीकी समिति ने लगभग 26 वर्षों तक कार्य किया। यह दावा किया गया कि सीमा संबंधी 97 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर लिया गया। शेष तीन प्रतिशत का समाधान करना उनकी क्षमता से परे था। उसमें कालापानी-लिम्पियाधुरा शामिल है—जो 370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा अतिक्रमण है; इसके अलावा 24 किलोमीटर का सुस्ता क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अन्य स्थान भी इसमें हैं। कुल मिलाकर, ऐसे लगभग 71 स्थान हैं जो 606 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल घेरते हैं। इस स्थिति के बने रहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक, सीमांकन के लिए पुराने मानचित्रों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता है।

काश! काठमांडू पोस्ट ने बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की पुस्तक 'द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड द शिफ्टिंग बॉर्डर्स ऑफ नेपाल' में बर्नार्डो माइकल द्वारा की गई टिप्पणी पर ग़ौर किया होता, 'आज भी, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों की उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आधुनिक सीमाओं के निर्धारण की यह परियोजना सदैव एक 'अधूरी परियोजना' ही बनी रहेगी।'

नेपाल के लिए मुश्किल यह है कि लिपुलेख के मुद्दे पर चीन उसके साथ नहीं खड़ा है। लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन भारत का है, उसकी पुष्टि 15 मई, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ व्यापार समझौता है। यह भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था, जिस पर चीनी प्रधानमंत्री ली कछियांग के साथ पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें औपचारिक रूप से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार पर सहमति बनी थी। 41-सूत्री संयुक्त बयान के बिंदु 28 में लिपुलेख दर्रे (कियांगला) को औपचारिक रूप से एक द्विपक्षीय सीमा व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में मान्यता दी गई थी।

तब नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि भारत और चीन ने उसकी सहमति के बिना, उसके दावे वाले क्षेत्र से होकर व्यापार करने पर बातचीत की है। बाद के दिनों में नेपाल के तीन प्रधानमंत्रियों केपी शर्मा ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा ने लिपुलेख-लिम्पियाधुरा के बॉल को जमकर खेला। बालेन्द्र शाह से पहले पीएम ओली इस मुद्दे को उठाने 3 सितम्बर, 2025 को पेइचिंग में आहूत थिएनमान चौक विजय दिवस समारोह तक गए लेकिन, चीनी सत्ता प्रतिष्ठान ने उसे अनसुना कर दिया। चीन और भारत तय कर चुके थे कि लिपुलेख-लिम्पियाधुरा ट्राइजंक्शन के बरास्ते जून, 2026 में उभयपक्षीय व्यापार होना है।

बहरहाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है। अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी क़ब्ज़ा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है। कई सांसद यह चाह रहे हैं कि संसद के रिकार्ड से यह बयान स्पन्ज़ किया जाये। लेकिन, ज़ुबान से निकली बात और कमान से छूटे तीर की वापसी नहीं हो सकती।

नेपाली मीडिया भी हतप्रभ है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट प्रधानमंत्री शाह के बयान को अपरिपक्व मानते हुए लिखता है, 'अगर उन्होंने 'अतिक्रमण' शब्द के बजाय 'सीमा-पार के कब्ज़े' शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो कोई विवाद नहीं होता। दूसरा, नेपाल और भारत के बीच उभयपक्षीय मामले में ब्रिटेन को शामिल करने की इच्छा भी गलत है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह बाउंडरी बातचीत में किसी तीसरे पक्ष को कभी नहीं कबूल करेगा, चाहे वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल के साथ हो।'

जो भी हो, बालेन्द्र शाह का यह बयान भारत-नेपाल संबंधों का कड़वा सच है, जिसे वहां के तथाकथित राष्ट्रवादी नेता और प्रतिक्रियावादी पचा नहीं पा रहे हैं। काठमांडू स्थित सिंह दरबार के गर्भ में वो तमाम दस्तावेज़ गर्क़ हैं, जिसमें भूमिहरण संबंधी नक्शा और दस्तावेज़ों की हेराफेरी नेपाली नौकरशाहों ने समय-समय पर की है। नेपाली नेताओं की बौखलाहट की वजहें हैं। नेपाली संसद के निचले सदन में 13 जून, 2020 को लिपुलेख ट्राइजैक्शन की दावेदारी को सही ठहराने के लिए एक फर्जी चूचे नक्शा पास किया गया था। उसके सोर्स पर तत्कालीन सांसद सरिता गिरि ने सवाल किया, तो उनकी सदस्यता बर्खास्त कर दी गई।

नेपाल की लीडरशिप जिस 10 सूत्री सुगौली संधि को जपती रहती है, कम से कम उसके तीसरे और पांचवें बिंदु को ध्यान से पढ़ना चाहिए। पांचवें बिंदू में लिखा है— 'नेपाल के राजा, उनके वारिस और उत्तराधिकारी काली नदी के पश्चिम में स्थित सभी दावों का परित्याग करेंगे।' भूलवश या अपरिपक्वता कहें, बालेन्द्र शाह ने जिस विवादित जिन्न को बोतल से बाहर निकाल दिया है, उसे वापस बोतल में डालना अब मुश्किल होगा।

लेखक भू-राजनीतिक मामलों के पत्रकार हैं।

कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पुरानी गलतियां नहीं दोहराई

नीरजा चौधरी

राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो नहीं कर पाई थी, कर्नाटक में उसने कर दिखाया। राजस्थान में पार्टी ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट को बारी-बारी से मुख्यमंत्री बनाने का वादा किया था, लेकिन गहलोत ने इसे नहीं होने दिया। उन्होंने तो पार्टी को ही चुनौती दे दी थी।

पार्टी आलाकमान पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष तक नहीं बना पाया है, ताकि वे 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के स्वाभाविक उत्तराधिकारी बन सकें। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जब पार्टी ने आधे कार्यकाल के लिए टीएस सिंहदेव को राज्य की कमान सौंपनी चाही तो ज्यादातर विधायकों का समर्थन लेकर बैठे भूपेश बघेल ने भी ऐसे प्रयास को नाकाम कर दिया था।

इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को गुटबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा और 2023 में वो सत्ता गंवा बैठी। इसके उलट, कर्नाटक में सत्ता हस्तांतरण शांति से हुआ। इसका श्रेय सिद्धारमैया को जाता है, जो अपने उपमुख्यमंत्री के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ने पर राजी हो गए।

किसी राजनेता के लिए ऐसा करना आसान नहीं होता। इस बार आलाकमान भी इसको लेकर स्पष्ट रहा कि वह क्या चाहता है। शीर्ष नेतृत्व में एकजुटता दिखी और अपना निर्णय मनवाने की दृढ़ता भी। दक्षिण में कांग्रेस के बढ़ते दबदबे को देखते हुए कर्नाटक को लेकर उसके दांव आज अधिक ऊंचे हैं।

गहलोत और बघेल की तरह सिद्धारमैया के पास भी उनके समर्थक विधायकों का बहुमत था। लेकिन वे बगावत के बजाय हाईकमान के निर्देश का पालन करते नजर आए। भले उन्हें भविष्य में इसका सियासी फायदा मिले या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी साख जरूर बना ली है।

वे जानते थे कि डी.के. शिवकुमार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बना रहे थे। ऐसे में हालात सिद्धारमैया और डीकेएस के अलावा कांग्रेस के लिए भी उलझन भरे हो सकते थे। एक वक्त तो डीकेएस की भाजपा से भी नजदीकियां बढ़ने की खबरें आई थीं। शायद यह भी हाईकमान पर दबाव बढ़ाने के लिए ही होगा।

सिद्धारमैया ने हाईकमान के बदले मूड को भी भांप लिया था। कुरुबा ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सिद्धारमैया जनाधार वाले नेता हैं और 'अहिंदा' (पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित) गठबंधन के सूत्रधार माने जाते हैं, जिसने कांग्रेस को मजबूत स्थिति में बनाए रखा।

इसी की बदौलत सिद्धारमैया दो बार विपक्ष के नेता बने और दो बार मुख्यमंत्री भी रहे। उनके सियासी कद और ओबीसी पहचान की वजह से ही राहुल गांधी लगातार उनका समर्थन करते रहे हैं। लेकिन अब कल यानी 3 जून को डीकेएस मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और उनके नाम का प्रस्ताव सिद्धारमैया ने ही रखा।

सिद्धारमैया के गद्दी छोड़ने का मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि वे राजनीति भी छोड़ रहे हैं। इसके उलट, उन्होंने संकेत दे दिया है कि वे एक विधायक के तौर पर कर्नाटक में सक्रिय रहेंगे। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सीट की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में जाने से इनकार कर दिया।

हालांकि, यह कहना मुश्किल है कि यदि कांग्रेस उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की पेशकश करेगी तो वे उसे भी ठुकरा देंगे या नहीं। खरगे का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है और ऐसे में ओबीसी समुदाय से आने वाला कोई अध्यक्ष राहुल की राजनीति को नई गति दे सकता है।

मुख्यमंत्री पद छोड़ने से कुछ घंटे पहले ही सिद्धारमैया ने कर्नाटक की जाति जनगणना को मंजूरी दे दी, जिसका आदेश उन्होंने ही 2025 में दिया था। ऐसा करके उन्होंने डीकेएस के सामने एक कठिन सियासी चुनौती छोड़ दी है। यदि डीकेएस इसे स्वीकार करते हैं, तो उनका अपना वोक्कालिगा समुदाय नाराज हो सकता है। यदि इसे ठंडे बस्ते में डालते हैं तो ओबीसी समुदाय नाराज होकर फिर सिद्धारमैया के पक्ष में लामबंद हो सकता है।

कर्नाटक का उदाहरण बताता है कि कांग्रेस में निर्णय करने की बात आए तो राहुल और प्रियंका अब अधिक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। इससे दक्षिण भारत में कांग्रेस ने खुद को और मजबूती ही प्रदान की है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

टूटे समाजों में भरोसा लौटाने के लिए सम्मान

दिनेश भारद्वाज

अभिलाषा की कहानी केवल एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जहां बेटियां सीमाएं नहीं, संभावनाएं देखती हैं। जहां वर्दी केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का चेहरा भी बन रही है।

दुनिया में सैनिकों की पहचान अक्सर युद्ध और सीमाओं से जुड़ी होती है। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं, जो वर्दी पहनकर केवल सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि भरोसा, संवेदनशीलता और उम्मीद भी बांटते हैं। भारतीय सेना में मेजर अभिलाषा बराक आज ऐसी ही पहचान बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' के लिए चुना है।

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और किशोरियों के बीच विश्वास निर्माण, संवाद और संवेदनशील नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उपलब्धि सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की सफलता नहीं है। यह उस भारत की कहानी है, जहां बेटियां अब केवल सपने नहीं देख रहीं, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं।

अभिलाषा बराक का संबंध हरियाणा के रोहतक से है। उनका बचपन सेना के अनुशासन और देशभक्ति के माहौल में बीता। उनके पिता कर्नल एस. ओम सिंह भारतीय सेना में रहे हैं। परिवार की सैन्य परंपरा ने अभिलाषा के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। तभी उनके भीतर देशसेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन का लक्ष्य बनती चली गई। हालांकि उनका जन्म तमिलनाडु के वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में हुआ, लेकिन परिवार की जड़ें रोहतक से जुड़ी रहीं।

अभिलाषा ने जब भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनकर इतिहास रचा, तब हरियाणा ने उन्हें गर्व के साथ 'रोहतक की बेटी' कहा। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया।

साल 2022 भारतीय सेना के इतिहास में एक अहम मोड़ आया, जब अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर बनीं। यह भारतीय सेना के बदलते स्वरूप का प्रतीक भी थी। लंबे समय तक सेना के लड़ाकू और एविएशन विंग को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा।

महिलाओं की भूमिका सीमित समझी जाती थी। उन्होंने यह साबित किया कि साहस, नेतृत्व और क्षमता का कोई लिंग नहीं होता। उनकी इस उपलब्धि ने देशभर की हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि अब भारतीय सेना में महिलाओं के लिए कोई 'सीलिंग' नहीं बची है।

आज संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन केवल सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष प्रभावित समाज में भरोसा बहाल करना भी है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के तहत तैनात भारतीय बटालियन में अभिलाषा बराक महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। युद्ध प्रभावित इलाकों में महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। ऐसे क्षेत्रों में महिला सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे स्थानीय महिलाओं से ज्यादा सहज संवाद स्थापित कर पाती हैं। अभिलाषा बराक ने लेबनान में महिलाओं और किशोरियों के साथ संपर्क कार्यक्रम चलाए, सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और शांति सैनिकों को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने यह दिखाया कि एक सैनिक केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि सामाजिक विश्वास का चेहरा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनके इसी मानवीय नेतृत्व और संवेदनशील कार्यशैली को सम्मानित करने का फैसला किया।

मेजर अभिलाषा बराक इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी हैं। उनसे पहले सुमन गुवानी और राधिका सेन भी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित हो चुकी हैं। मेजर सुमन गवानी को दक्षिण सूडान में महिलाओं के अधिकारों और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए सम्मान मिला था। वहीं मेजर राधिका सेन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सामाजिक भरोसा कायम करने की दिशा में अहम कार्य किया। अब अभिलाषा बराक का इस सूची में शामिल होना भारतीय महिला सैन्य नेतृत्व की निरंतर बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है।

एक समय था जब हरियाणा को बेटियों के प्रति रूढ़ सोच वाले राज्य के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज वही हरियाणा खेल, सेना, विज्ञान और प्रशासन में देश को नई पहचान देने वाली बेटियां दे रहा है। अभिलाषा बराक इसी बदलाव का सबसे मजबूत चेहरा हैं। उनकी उपलब्धि यह भी दिखाती है कि यदि अवसर, शिक्षा और विश्वास मिले तो भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं।

अभिलाषा बराक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने सैनिक की कठोर छवि के भीतर मानवीय संवेदना को जीवित रखा। उन्होंने दिखाया कि शांति मिशन केवल सीमाओं की निगरानी नहीं, बल्कि टूटे हुए समाज में भरोसा लौटाने की जिम्मेदारी भी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 'जेंडर एडवोकेट' यानी लैंगिक समानता की पैरोकार के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया।

आज जब युवा पीढ़ी त्वरित सफलता और सोशल मीडिया की चमक से प्रभावित है, तब मेजर अभिलाषा बराक जैसी शख्सियतें यह याद दिलाती हैं कि असली पहचान मेहनत, अनुशासन और सेवा से बनती है। अभिलाषा की कहानी केवल एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जहां बेटियां सीमाएं नहीं, संभावनाएं देखती हैं। जहां वर्दी केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का चेहरा भी बन रही है।

जिनके इलाज से टिके मर्ज, निकले मरीज

गांवों की अपनी मजबूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद डाक्टर शहरों में टिके रहना चाहते हैं और गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों की चल निकलती है। कहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अगर वही फर्जी निकल जाए, तब तो भगवान ही मालिक है। तब तबीयत में सुधार के लिए भगवान को भेजी गई अर्जी भी काम नहीं आती। मर्ज रह जाता है, मरीज़ निकल लेता है। उम्रदराज जनकलाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। नियमित जांचें कराते हैं। एक दिन इसी मंशा से किसी संजीवनी क्लीनिक पर पहुंचे।

लंबी प्रतीक्षा के बाद एक डॉक्टर प्रकट हुआ। उसने उन पर एक नज़र डाली और सीधे पर्ची पर उतर आया। ताबड़तोड़ कलम घसीटते हुए बोला, 'आप तो बिल्कुल ठीक हैं, बस अंडरवेट हैं। सुबह की ताज़ी हवा खाएं और ये दवाएं लीजिए। थोड़ी महंगी हैं। ठीक हो जाएंगे।' जनकलाल ने अपने बचे-खुचे दांतों तले अंगुली दबा ली, डॉक्टर तो पहुंचा हुआ मालूम पड़ता है! बिना जांचे पर्चा लिख दिया?

जनकलाल खुद ही अपनी नब्ज़ टटोलते हुए विचारने लगे- मैं तो जिंदगीभर से ऐसे ही हूं, दुबला-पतला! फिर उन्होंने डॉक्टर को देखा। वह मुंह में जर्दा दाबे सीकिया पहलवान लगता था! वे बोले, 'आप भी तो अंडरवेट हैं डॉक्टर साब!' डॉक्टर मुख ऊपर करके हंसा, वरना पीक बाहर आ जाती। फिर ठसके से पूछा, 'डॉक्टर मैं हूं या आप?' जनकलाल सकपका गए, 'जी, आप। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया।' जनकलाल के जवाब से डॉक्टर को भरोसा आया कि वही डॉक्टर है, सो हो... हो... कर हंसा, 'वो क्या है कि मेरी तबीयत जरा खराब है?' यह मामला हास्यास्पद-सा लगता है, लेकिन संजीवनी क्लीनिकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे डॉक्टरों के मामले को देखते हुए सच जान पड़ता है।

झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में कौन नहीं जानता। पर कौन जानता था कि फर्जी डिग्री धारक, झोलाछाप डॉक्टरों की भांति क्लीनिकों में बैठकर मरीजों की जान से खेलने लगेंगे। गांवों में आज भी झोलाछाप डॉक्टर पाए जाते हैं। एक गांव में रोजमर्रा की खरीदारी के लिए भरने वाले साप्ताहिक बाजार के दिन, एक इंजेक्शन वाला झोलाछाप डॉक्टर काफी चर्चा में रहा। वह बीच बाजार, गांव की सड़क के किनारे पुलिया की सुरक्षा दीवार के शीर्ष चबूतरे पर मरीज़ को लिटाता और बिना किसी झंझट मरीज के कपड़ों के ऊपर से ही इंजेक्शन ठूंस कर इलाज करता था! मरीज अपने नितंब दबाए फीस चुकाते और निकल लेते थे।

बहरहाल, गांवों की अपनी मजबूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद डाक्टर शहरों में टिके रहना चाहते हैं और गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों की चल निकलती है। क्लीनिकों के हालिया फर्जीवाड़ा के चलते झोलाछाप कॉकरोच शहरों में भी सुरसुराने लगे हैं?

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

जिला चिकित्सालय में इंटरकॉम सुविधा बहाल करने की मांग

दुर्ग। जिला चिकित्सालय में मरीजों और उनके परिजनों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इंटरकॉम सेवा को पुन: प्रारंभ करने की मांग की गई है। इस संबंध में जिला चिकित्सालय की जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप ठाकुर, मानद सदस्य प्रशांत डोंगांवकर तथा रेड क्रॉस सदस्य दुष्यंत देवांगन ने सिविल सर्जन सह अधीक्षक डॉ. ए.के. मिंज को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि 500 बिस्तरों वाले जिला चिकित्सालय में प्रतिदिन 1000 से अधिक मरीज स्थानीय एवं अन्य जिलों से उपचार के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल के विभिन्न विभागों के बीच त्वरित संवाद और समन्वय के लिए इंटरकॉम सुविधा अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान समय में आपातकालीन विभाग तथा मातृत्व एवं शिशु विभाग में इंटरकॉम सेवा निष्क्रिय अवस्था में है, जिससे कार्य संचालन और मरीजों की सुविधा प्रभावित हो रही है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि पूर्व में जिला चिकित्सालय में इंटरकॉम सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन वर्तमान में यह सेवा बंद है। अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने तथा आपात परिस्थितियों में त्वरित संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए इंटरकॉम सेवा को शीघ्र बहाल किए जाने की मांग की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का आयुक्त ने किया औचक निरीक्षण

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के एएचपी घटक के तहत सरस्वती नगर में निर्मित 522 आवासीय इकाइयों का नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने औचक निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति और उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, सहायक अभियंता संजय ठाकुर, उपअभियंता हरिशंकर साहू, निर्माण एजेंसी के प्रतिनिधि तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने परियोजना में चल रहे निर्माण कार्यों, मूलभूत सुविधाओं एवं हितग्राहियों को उपलब्ध कराई जा रही व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने निर्माण एजेंसी को निर्देशित किया कि शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य प्रत्येक पात्र परिवार को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है, इसलिए कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्यों को तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, सड़क एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। समस्याओं और सुझावों की जानकारी भी ली।

नवीन कंपोजिट बिल्डिंग बनेगी सुशासन, पारदर्शिता और आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का नया केंद्र : गजेन्द्र यादव

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी द्वारा दुर्ग जिला मुख्यालय में नवीन कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण की गई घोषणा को शीघ्र धरातल पर उतारने की दिशा में आज महत्वपूर्ण पहल हुई। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के साथ कलेक्टर अभिजीत सिंह, पीडब्ल्यूडी, अपर कलेक्टर, एसडीएम तथा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का विस्तृत निरीक्षण किया।

सुबह लगभग 10 बजे से एक घंटे तक चले निरीक्षण के दौरान शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव एवं अधिकारियों ने कलेक्टरेट परिसर का पैदल भ्रमण कर वर्तमान भवनों, पार्किंग व्यवस्था, भू-अभिलेख कार्यालय, निर्वाचन शाखा, एनआईसी, विभिन्न विभागीय कार्यालयों तथा उपलब्ध भूमि का बारीकी से अवलोकन किये। इस दौरान अधिकारियों ने नवीन कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण से संबंधित विभिन्न तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की।

निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भवन में सभी विभागों के कार्यालयों को एकीकृत रूप से स्थापित करने, आधुनिक सुविधाओं से युक्त मीटिंग हॉल, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, सुव्यवस्थित प्रवेश द्वार, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, डिजिटल प्रशासनिक व्यवस्था तथा नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक अधोसंरचना विकसित करने कहा गया। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि कलेक्टरेट परिसर में संचालित सभी विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भवन का ड्राइंग एवं डिजाइन तैयार किया जाए। उन्होंने शीघ्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार कर शासन को प्रस्तुत करने तथा निर्माण कार्य प्रारंभ करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की मंशा के अनुरूप दुर्ग में बनने वाली यह नवीन कंपोजिट बिल्डिंग केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं होगी, बल्कि आने वाले कई दशकों तक सुशासन, पारदर्शिता और जनसुविधा का सशक्त केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के एक ही परिसर में संचालित होने से आम नागरिकों को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे तथा प्रशासनिक कार्यों में भी अधिक समन्वय और गति आएगी।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में दुर्ग निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। आईटी पार्क, इंडोर स्विमिंग पूल, अधोसंरचना विकास कार्यों के बाद अब आधुनिक कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण दुर्ग को एक सुव्यवस्थित एवं आधुनिक प्रशासनिक शहर के रूप में नई पहचान प्रदान करेगा। यह भवन विकसित हो रहे नए दुर्ग की पहचान और सुशासन का प्रतीक बनेगा।

निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रस्तावित निर्माण कार्य के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए तथा निश्चित समय अवधि में पूर्ण करने पर चर्चा किये।

बीएसपी द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर-2026 का समापन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर-2026 का समापन 30 मई 2026 को संपन्न हुआ। 11 मई से 30 मई 2026 तक आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में विभिन्न आयु वर्ग के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए खेल कौशल के विकास, शारीरिक क्षमता संवर्धन एवं खेल भावना के विस्तार का लाभ प्राप्त किया।

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक पवन कुमार थे। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी ए.बी. श्रीनिवास, महाप्रबंधक मनोज कुमार दुबे, महाप्रबंधक शाहिद अहमद, उप महाप्रबंधक एवं ओलंपियन राजेन्द्र प्रसाद तथा उप प्रबंधक (क्रीड़ा, सांस्कृतिक एवं नागरिक सुविधाएं) अभिजीत भौमिक सहित संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी, प्रशिक्षक, प्रतिभागी एवं अभिभावक उपस्थित रहे।

ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर-2026 के अंतर्गत कुल 18 खेल विधाओं का संचालन किया गया। शिविर के लिए कुल 1910 पंजीयन प्राप्त हुए, जिनमें से 1822 प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण कार्य में कुल 88 प्रशिक्षकों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को अनुभवी कोचों द्वारा तकनीकी प्रशिक्षण के साथ-साथ शारीरिक दक्षता, अनुशासन, टीम भावना तथा खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने अपने संबोधन में प्रतिभागियों के उत्साह एवं खेलों के प्रति समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि खेल बच्चों एवं युवाओं के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर प्रतिभाओं को निखारने तथा उन्हें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों एवं आयोजन से जुड़े कार्मिकों को सफल आयोजन के लिए बधाई दी।

समारोह के दौरान प्रतिभागियों द्वारा विभिन्न खेल विधाओं में अर्जित कौशल का प्रदर्शन भी किया गया, जिसे उपस्थित अतिथियों एवं अभिभावकों ने सराहा। इस अवसर पर प्रशिक्षकों एवं प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई।

महापौर अलका बाघमार ने किया सघन निरीक्षण विकास एवं सफाई व्यवस्था का लिया जायजा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत आज महापौर अलका बाघमार ने लोककर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, वित्त विभाग प्रभारी नरेंद्र बंजारे, पार्षद रेशमा सोनकर एवं पार्षद सरस निर्मलकर के साथ वार्ड क्रमांक 57 एवं 58 का लगभग दो घंटे तक सघन निरीक्षण कर क्षेत्र की साफ-सफाई, जल निकासी व्यवस्था, नाला-नाली निर्माण तथा नागरिक सुविधाओं का जायजा लिया।

निरीक्षण की शुरुआत वार्ड क्रमांक 57 में श्रीराम मैरिज पैलेस क्षेत्र से की गई। महापौर ने गलियों एवं मोहल्लों में पहुंचकर नाला एवं नालियों की स्थिति का अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को नियमित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वर्षाकाल को देखते हुए जलभराव की स्थिति निर्मित न हो, इसके लिए नालियों की सफाई तथा आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किए जाएं।

निरीक्षण के दौरान जहां-जहां नाली निर्माण एवं नाला किनारे सफाई कार्य की आवश्यकता पाई गई, वहां तत्काल कार्ययोजना बनाकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। नाला निर्माण से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के लिए महापौर ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर लंबित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कराने कहा। नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने।

विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर महापौर, आयुक्त एवं पर्यावरण प्रभारी की नागरिकों से अपील

एक पौधा प्रकृति के नाम, स्वच्छ और हरित दुर्ग के निर्माण में दें अपना योगदान

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत आगामी 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर महापौर अलका बाघमार,आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं पर्यावरण प्रभारी काशीराम कोसरे ने शहरवासियों से पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल शासन या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। यदि हम आज प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण प्रदान कर सकेंगे।

महापौर, आयुक्त एवं पर्यावरण प्रभारी ने नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, सिंगल-यूज़ प्लास्टिक का उपयोग पूर्णत: बंद करने, जल एवं ऊर्जा संरक्षण को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने तथा स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की छोटी-छोटी आदतें भी समाज और प्रकृति के लिए बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण कराने का अवसर है। आज बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण असंतुलन की स्थिति निर्मित हो रही है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आना होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ अथवा अन्य विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं और उसके वृक्ष बनने तक उसकी नियमित देखभाल करें। एक पौधा न केवल पर्यावरण को शुद्ध करता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन का आधार भी बनता है।

राजहरा माइंस हॉस्पिटल में 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफल आयोजन

श्रीकंचनपथ समाचार

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के राजहरा माइंस हॉस्पिटल में दिनांक 01 जून 2026 को 24वें मेगा मेडिकल कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य राजहरा एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सा परामर्श, स्वास्थ्य जांच तथा आवश्यक उपचार सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। शिविर में विभिन्न विशेषज्ञताओं के चिकित्सकों की बहु-विषयक टीम द्वारा व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गईं।

चिकित्सा शिविर के दौरान लगभग 650 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं परामर्श किया गया। लाभार्थियों को हृदय रोग, मेडिसिन, अस्थि रोग, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र रोग, कान-नाक-गला (ईएनटी), त्वचा रोग, दंत चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा तथा दर्द प्रबंधन सहित विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ परामर्श एवं उपचार संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। शिविर के दौरान 25 इंट्रा-आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाए गए तथा 6 मरीजों को प्लास्टर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

इस मेगा मेडिकल कैंप में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय की मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. विनीता द्विवेदी के नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सेवाएं प्रदान कीं। टीम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं विभागाध्यक्ष (सर्जिकल ट्रॉमा) डॉ. कौशलेंद्र ठाकुर, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. चंदन दास, मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. प्रमोद बिनयके, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. इमैनुअल मैसी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. कौशिक किशोर, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रभदीप कौर, दंत शल्य चिकित्सक डॉ. वनिता शर्मा, सामान्य शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. धीरज शर्मा, दर्द प्रबंधन विशेषज्ञ डॉ. शिखा अग्रवाल, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. शशांक अग्रवाल, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका शिवप्पा तथा नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आरती जैन शामिल थीं। इसके अतिरिक्त डीएनबी रेजिडेंट्स डॉ. शुभम (ऑर्थोपेडिक्स), डॉ. शालिनी (प्रसूति एवं स्त्री रोग), डॉ. श्रेयस (नेत्र रोग) एवं डॉ. पूर्णिमा (मेडिसिन), सहायक प्रबंधक श्रीमती देवकी साहू, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट श्री कल्लोल मैती तथा फिजियोथेरेपिस्ट श्री दिग्विजय ने भी शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया नेतृत्व में विशेषज्ञ चिकित्सकों, डीएनबी रेजिडेंट्स, पैरामेडिकल कर्मियों एवं सहयोगी स्टाफ ने सक्रिय भूमिका निभाई।

दुर्ग जिले की 102 ग्राम पंचायतों में 112 नवा तरिया एवं तालाब गहरीकरण कार्य स्वीकृत

मोर गांव मोर पानी महाभियान से जल संरक्षण और रोजगार को मिल रही नई दिशा

श्रीकंचनपथ समाचार

दुर्ग। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ किए गए मोर गांव मोर पानी महाभियान के अंतर्गत दुर्ग जिले में जल संरक्षण, भू-जल संवर्धन और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक स्तर पर नवा तरिया एवं तालाब गहरीकरण कार्य संचालित किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जनपद पंचायत धमधा, दुर्ग एवं पाटन की कुल 102 ग्राम पंचायतों में 112 कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशन में संचालित इन निर्माण कार्यों को आगामी 15 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्राम पंचायतों के सरपंच, उपसरपंच एवं पंचों के नेतृत्व में पंजीकृत श्रमिक पूरी सक्रियता के साथ निर्माण कार्यों में जुटे हुए हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के

अवसर बढ़े हैं तथा श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर कार्य उपलब्ध हो रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि नवा तरिया एवं तालाब गहरीकरण कार्यों का चयन ग्रामसभा की सहमति से किया गया है। भूमिपूजन के बाद से ही निर्माण कार्य तेज गति से चल रहा है और बारिश से पहले इन्हें पूरा करने के लिए ग्रामीण एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से प्रत्येक पात्र अकुशल श्रमिक परिवार को मांग के अनुरूप रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

मनरेगा के तहत जिले की 102 ग्राम पंचायतों में 112 नवा तरिया एवं तालाब गहरीकरण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें जनपद पंचायत धमधा की 40 ग्राम पंचायतें, जनपद पंचायत दुर्ग की 49 ग्राम पंचायतें तथा जनपद पंचायत पाटन की 13 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत तालाबों का गहरीकरण, नवा तरिया निर्माण एवं जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न संरचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। इन निर्माण कार्यों से बड़ी संख्या में ग्रामीण श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वहीं वर्षा जल के अधिकतम संचयन से भू-जल स्तर में सुधार तथा कृषि एवं मत्स्य पालन गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

जनपद पंचायत धमधा की अछोली, अगार, अरसी, बरहापुर, बसनी, बिरझापुर, बिरोदा, बोरी, देवरी सहित 40 ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायत दुर्ग की अण्डा, अंजोरा, बोरई, चांगोरी, धनोरा, पुरई, थनौद सहित 49 ग्राम पंचायतों तथा जनपद पंचायत पाटन की करेला, असोगा, गब्दी, गाड़ाडीह, गुढ़ियारी, कानाकोट, करसा, केसरा, रवेली, रेंगाकठेरा, सिकोला, तर्रा एवं तेलीगुण्डरा सहित 13 ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत तालाब गहरीकरण सह नवा तरिया निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यों से जल संरक्षण के साथ ग्रामीणों को व्यापक स्तर पर रोजगार उपलब्ध हो रहा है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दुर्ग बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि मोर गांव मोर पानी महाभियान के अंतर्गत स्वीकृत नवा तरिया एवं तालाब गहरीकरण कार्य जिले में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इन तालाबों के निर्माण पूर्ण होने के बाद प्रत्येक संरचना में 10 हजार घनमीटर से अधिक जल भंडारण क्षमता विकसित होगी। इससे वर्षा जल का बेहतर संचयन होने के साथ भू-जल स्तर में भी सुधार आएगा। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात तालाबों का संचालन स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाएगा, जिससे महिलाओं को आजीविका के नए अवसर प्राप्त होंगे तथा उनकी आर्थिक भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक तालाब में प्रतिवर्ष लगभग 13 से 15 क्विंटल मत्स्य उत्पादन की संभावना है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में अतिरिक्त वृद्धि होगी।

Since 1972
CROWN-TV
Choice Of Millions
LED / Washing Machine
Cooler / Fridge
Available All Size
CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 13
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line
Mob.: 98262 52372

खास-खबर

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय सम्मान

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री सूर्यघर : मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आयोजित **"Month of Solar"** अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाना राज्य के लिए अत्यंत गौरव और प्रसन्नता का विषय है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि राज्य में स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में किए जा रहे सतत प्रयासों का प्रमाण है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मध्यम उपभोक्ता आधार वाले राज्यों की श्रेणी में सर्वाधिक वेंडर रजिस्ट्रेशन के मामले में छत्तीसगढ़ ने देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए राज्य का चयन पीएम सूर्यघर एक्सीलेंस अवार्ड हेतु किया गया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऊर्जा क्षेत्र में राज्य की सक्रियता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसहभागिता का सकारात्मक परिणाम है। मुख्यमंत्री साय ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए ऊर्जा विभाग, क्रेडा, विद्युत वितरण कंपनियों, सभी अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहयोगी संस्थाओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

सुशासन तिहार: दुरती शिविर में 274 आवेदनों पर हुई सुनवाई

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के सुशासन और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान के संकल्प को साकार करते हुए सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत सूरजपुर जिला के विकासखंड प्रतापपुर के ग्राम पंचायत दुरती में समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दुरती सेक्टर की 19 पंचायतों के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी तथा प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण किया। शिविर के दौरान 14 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड, 9 वृद्धजनों को पेंशन स्वीकृति पत्र तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा 4 हितग्राहियों को पांच-पांच लाख रुपये तक के उपचार की सुविधा प्रदान करने वाले आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए।

भीषण गर्मी में राहत: हैंडपंप सुधार कार्य से ग्रामीणों को मिल रही निर्बाध पेयजल सुविधा

रायपुर। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी दिशा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न गांवों में खराब एवं बंद पड़े हैंडपंपों की मरम्मत और रखरखाव का कार्य युद्धस्तर पर किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल रही है। इसी क्रम में विकासखंड मनेन्द्रगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलोखन के ग्राम तिलोखन में विभागीय टीम द्वारा हैंडपंपों का निरीक्षण एवं मरम्मत कार्य किया गया। लंबे समय से प्रभावित पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करते हुए हैंडपंपों को पुन: चालू किया गया, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुगम पेयजल उपलब्ध होने लगा है। गर्मी के मौसम में जल स्रोतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जिलेभर में विशेष अभियान चलाकर खराब हैंडपंपों की पहचान की जा रही है।

चार जिलों की समीक्षा: मुख्यमंत्री साय ने जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनसेवा पर दिया जोर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि समाधान शिविरों का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक अमला सकारात्मक सोच और सार्थक प्रयासों के साथ कार्य करे, ताकि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचे और सुशासन की भावना जमीन पर दिखाई दे। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत मंगलवार शाम कांकेर जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री साय ने कांकेर, कोण्डागांव, नारायणपुर और बस्तर जिलों में संचालित योजनाओं एवं विकास कार्यों की जिलावार समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यशैली अपनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए ताकि हितग्राहियों को पक्के आवास का लाभ मिल सके। उन्होंने खरीदी केन्द्रों से धान उठाव की प्रक्रिया तेज करने तथा स्थानीय स्तर पर धान मिलिंग को बढ़ावा देने के लिए युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि खरीफसीजन को देखते हुए खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने किसानों को नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि और एग्रीस्टैक पोर्टल में पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री साय ने मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तैयारी के साथ सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना, शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव, सिकल सेल स्क्रीनिंग तथा मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी-टू-ईट तैयार करने का कार्य देने, कुपोषण मुक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या बढ़ाने तथा सभी पात्र महिलाओं तक महतारी वंदन योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल आपूर्ति पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट की अनिवार्यता को लेकर निरंतर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। साथ ही डायल 112 के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया। बैठक में मुख्यमंत्री साय ने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम जनमन, बिहान योजना, तेंदूपत्ता खरीदी, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जल जीवन मिशन, अटल डिजिटल सेवा केन्द्र, ई-ऑफिस क्रियान्वयन, डीएमएफ कार्यों, शिक्षा गुणवत्ता, सड़क अवसंरचना और कानून-व्यवस्था से जुड़े विभिन्न विषयों पर विभागवार समीक्षा की तथा जिलों में प्रगति की जानकारी ली।

सुशासन तिहार में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे बीजापुर के सुदूर गांव कोण्डापल्ली : चौपाल में सुनीं ग्रामीणों की समस्याएं

रायपुर। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यहां आयोजित जनचौपाल में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं, योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति जानी तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से मुलाकात कर उनके जीवन में आए सकारात्मक बदलावों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच विश्वास को और मजबूत करने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और किसी भी जरूरतमंद को अपने अधिकारों एवं सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े। इसी भावना के साथ सरकार स्वयं गांव-गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रही है और उनके समाधान का प्रयास कर रही है।

जनचौपाल के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया तथा हितग्राहियों को वनाधिकार मान्यता पत्र, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, श्रम कार्ड, किसान हितग्राही योजनाओं सहित विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ वितरित किए। उन्होंने लाभार्थियों से चर्चा कर योजनाओं के प्रभाव और उनके अनुभवों की जानकारी भी प्राप्त की। ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों एवं शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी योजना की वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी जब उसका लाभ पात्र व्यक्ति तक सही समय पर पहुंचे और आमजन को शासन की संवेदनशीलता का अनुभव हो। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।

जब मुख्यमंत्री रुके एक छोटी-सी किराना दुकान पर... और सामने थी बदलाव की बड़ी कहानी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचे। चौपाल के लिए जा रहे मुख्यमंत्री का काफिला अचानक एक छोटी-सी किराना दुकान के सामने रुक गया। बाहर से देखने पर यह एक सामान्य दुकान थी, लेकिन उसके भीतर संघर्ष, साहस और बदलाव की एक असाधारण कहानी छिपी थी।यह दुकान आत्मसमर्पित दंपति मासा तामो और जयमोती की थी।

मुख्यमंत्री दुकान के भीतर पहुंचे, दोनों से आत्मीयता से बातचीत की और उनके जीवन में आए बदलाव के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने दुकान से पानी की बोतल खरीदी और दोनों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता ही नए जीवन की सबसे बड़ी पहचान है।

मासा तामो का बचपन गरीबी और अभावों में बीता। बचपन में पिता का साया उठ गया और पढ़ाई का अवसर कभी नहीं मिला। वर्ष 2007 में परिस्थितियों के कारण वह नक्सली संगठन से जुड़ गया। उधर जयमोती की कहानी भी संघर्षों से भरी रही। बचपन में माता-पिता का निधन हो गया और जीवन की कठिन परिस्थितियों ने उन्हें भी उसी रास्ते की ओर धकेल दिया। संगठन में दोनों की मुलाकात हुई और वर्ष 2021 में उन्होंने विवाह कर लिया। लेकिन समय के साथ दोनों ने महसूस किया कि हिंसा का रास्ता उनके भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए उचित नहीं है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने साहसिक निर्णय लेते हुए आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया।

बीजापुर पुनर्वास केंद्र पहुंचने के बाद दोनों के जीवन में नया अध्याय शुरू हुआ। पहली बार उन्हें अक्षर ज्ञान मिला, कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला और शासन की विभिन्न योजनाओं से जोड़ा गया। राशन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैंक खाता और अन्य आवश्यक दस्तावेज बनवाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्षम योजना के तहत जयमोती को एक लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ। इसी सहायता से कोण्डापल्ली में उनकी छोटी-सी किराना दुकान शुरू हुई।

मुख्यमंत्री से चर्चा के दौरान मासा और जयमोती ने बताया कि अब वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर रहे हैं। दुकान से होने वाली आय से परिवार की जरूरतें पूरी हो रही हैं और भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि जीवन में ऐसा बदलाव आएगा, लेकिन सरकार की पुनर्वास नीति और प्रशासन के सहयोग ने उन्हें नई पहचान दी है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि मासा और जयमोती की कहानी केवल दो व्यक्तियों की कहानी नहीं, बल्कि बदलते बस्तर की कहानी है। यह इस बात का प्रमाण है कि अवसर, विश्वास और सहयोग मिलने पर कोई भी व्यक्ति मुख्यधारा में लौटकर सम्मानजनक जीवन जी सकता है।

इलेक्ट्रिक चाक ने बदली कुम्हार की जिंदगी, दोगुनी हुई आमदनी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। परंपरागत हुनर जब आधुनिक तकनीक से जुड़ता है तो बदलाव की नई कहानी जन्म लेती है। गरियाबंद जिले के फिंगेश्वर विकासखंड अंतर्गत ग्राम कोसमखुटा के कुम्हार नारद चक्रधारी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वर्षों से मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का भरण-पोषण करने वाले नारद को अब इलेक्ट्रिक चाक मिलने से उनकी आजीविका को नई गति मिली है।

छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड की ओर से नारद चक्रधारी को इलेक्ट्रिक चाक प्रदान किया गया। विधायक रोहित साहू और कलेक्टर बी.एस. उइके ने उन्हें यह आधुनिक उपकरण सौंपा। नारद बताते हैं कि पहले हाथ से चलने वाले पारंपरिक चाक पर घड़ा, मटका, सुराही, दीया, खिलौने, गमले और अन्य मिट्टी के बर्तन तैयार करने में काफी समय और मेहनत लगती थी। उत्पादन सीमित होने के कारण आय भी सीमित रहती थी। लेकिन इलेक्ट्रिक चाक मिलने के बाद उनकी कार्यक्षमता और उत्पादन में वृद्धि होगी।

वे पहले प्रतिमाह 10 से 12 हजार रुपये मूल्य के उत्पाद तैयार कर पाते थे, वहीं अब लगभग 20 हजार रुपये तक के उत्पाद बनाने लगे हैं। त्योहारों के मौसम, विशेषकर दीपावली के दौरान उनकी मासिक आय 22 से 25 हजार रुपये तक पहुंच जाती है। नारद चक्रधारी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चाक ने न केवल उनका श्रम कम किया है, बल्कि उनके पारंपरिक व्यवसाय को अधिक व्यवस्थित और लाभकारी भी बनाया है। उनके लिए यह केवल एक उपकरण नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य की नई उम्मीद है।

मोर गांव मोर पानी अभियान बना मिसाल: 'नवा तरिया आय के जरिया' से जल संरक्षण के साथ बढ़ रहा ग्रामीण रोजगार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से संचालित मोर गांव मोर पानी अभियान सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में शुरू की गई 'नवा तरिया आय के जरिया' पहल जल संरक्षण, सिंचाई विस्तार और ग्रामीण आजीविका सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनकर उभर रही है। कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन एवं जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर के नेतृत्व में जिले में नवीन तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। इन जल संरचनाओं का उद्देश्य वर्षा जल की प्रत्येक बूंद को संजोना, भूजल स्तर में सुधार लाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी जल स्रोत विकसित करना है।

जिले में वर्तमान में 12 नए तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें विकासखंड बलरामपुर में 2, कुसमी में 2, राजपुर में 1, रामचंद्रपुर में 4, शंकरगढ़ में 1 तथा वाड्रफनगर में 2 तालाब शामिल हैं। इनमें से 9 स्थानों पर निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। प्रत्येक निर्माण स्थल पर प्रतिदिन लगभग 40 से 50 श्रमिकों को रोजगार मिल रहा है, जिससे जल संरक्षण के साथ ग्रामीण परिवारों की आय में भी वृद्धि हो रही है।

तालाबों का निर्माण वैज्ञानिक पद्धति से किया जा रहा है। जल संग्रहण क्षमता को दीर्घकाल तक बनाए रखने के लिए इनलेट, आउटलेट और सिल्ट ट्रैप जैसी संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। इससे मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण होगा और जलधारण क्षमता बनी रहेगी। इन नवीन जल संरचनाओं से आने वाले वर्षों में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि, भूजल स्तर में सुधार तथा पशुओं के लिए वर्षभर पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित होने की संभावना है। अपनाने का अवसर मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी।

सुशासन तिहार के शिविरों में मिल रहा समस्याओं का त्वरित समाधान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप सुशासन तिहार के अंतर्गत प्रदेशभर में जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

इसी क्रम में आज जांजगीर-चांपा जिले के जनपद पंचायत बम्हनीडीह अंतर्गत ग्राम पंचायत कुम्हारीकला तथा नगर पंचायत बलौदा एवं नरियरा में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी नागरिकों ने भाग लेकर अपनी मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से नागरिकों को शासन की जनकल्याणकारी एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इस दौरान नवीन राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड, किसान किताब, बी-1 खसरा, मतदाता पहचान पत्र, नैनो डीएपी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज एवं सामग्रियों का वितरण किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत हितग्राहियों को चेक एवं प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को प्रतीकात्मक चाबियां सौंपकर उनके पक्के आवास के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में गर्भवती महिलाओं की गोदभराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार संपन्न कराया गया।

साथ ही उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं नागरिकों ने बाल विवाह मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेते हुए शपथ ग्रहण की। शिविर के दौरान विशेष स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया, जहां नागरिकों को एक्स-रे, रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल एवं हीमोग्लोबिन जांच सहित विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री ने बिहान की दीदियों को सौंपी आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत टाटा मैजिक वाहन

महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मिलेगी नई उड़ान, ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा होगी सुदृढ़

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत ग्राम चेरपाल में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के अंतर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए विकासखंड कुआकोंडा एवं कटेकल्याण के 8 संकुल स्तरीय संगठनों को आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत टाटा मैजिक सवारी वाहनों की चाबी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तथा स्व-सहायता समूहों की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर अधिकारियों ने जानकारी दी कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर सृजित करने के साथ-साथ दूरस्थ अंचलों में परिवहन सुविधाओं को मजबूत बनाना है। योजना के तहत प्रदाय किए गए प्रत्येक टाटा मैजिक वाहन के लिए लगभग 5 लाख रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है। इन वाहनों के संचालन से स्व-सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को नियमित आय का स्रोत प्राप्त होगा तथा ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में बताया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से जिले में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। वर्तमान में जिले के 41 हजार 110 परिवारों को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर स्वरोजगार एवं आयवर्धन गतिविधियों से जोड़ा गया है। समूह की महिलाएं कृषि आधारित गतिविधियों, पशुपालन, लघु उद्यम, वनोपज प्रसंस्करण तथा विभिन्न आजीविका गतिविधियों के माध्यम से अपनी आय में वृद्धि कर रही हैं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रदाय किए गए इन वाहनों के संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुलभ, सुरक्षित एवं किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इससे दूरस्थ गांवों का बाजारों, स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षणिक केंद्रों तथा जिला मुख्यालय से बेहतर संपर्क स्थापित होगा। साथ ही महिलाओं को वाहन संचालन एवं प्रबंधन के माध्यम से नियमित आय प्राप्त होगी, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला बनकर उभर रही हैं। उन्होंने कहा कि शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना से उन्हें न केवल रोजगार का अवसर मिलेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसेवा का एक नया माध्यम भी प्राप्त होगा।

लाल कपड़ों में राशा थडानी ने दिलाई मां रवीना टंडन की याद

'श्रीनिवास मंगपुरम' के इवेंट से वायरल हो रहा वीडियो

राशा थडानी हाल ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'श्रीनिवास मंगपुरम' के एक इवेंट में नजर आईं। यहां से उनका लुक वायरल हो रहा है। यूजर्स ने उनकी तुलना उनकी मां रवीना टंडन से की है।

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी फिल्म 'श्रीनिवास मंगपुरम' से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू कर रही हैं। इस फिल्म में वह महेश बाबू के भतीजे जय कृष्णा घट्टामनेनी के साथ नजर आएंगी। हाल ही में हैदराबाद में इस फिल्म का एक इंट्रोडक्शन इवेंट हुआ। इसमें दोनों कलाकारों का परिचय कराया गया।

इवेंट से राशा का लुक वायरल

इस इवेंट से राशा थडानी का लुक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स ने उनकी तुलना उनकी मां रवीना टंडन से की है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए इसके कैप्शन में लिखा गया 'ऐसा क्यों लगता है कि हम रवीना टंडन को देख रहे हैं?' वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि राशा थडानी लोगों के बीच से उठकर स्टेज पर आती हैं। इसके बाद अपने साथी कलाकार जय कृष्णा घट्टामनेनी को केक खिलाती हैं।

भावुक हुए जय कृष्णा घट्टामनेनी

आपको बता दें कि यह इंट्रोडक्शन इवेंट सुपरस्टार कृष्णा की जयंती के मौके पर आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए, जय कृष्णा अपने दादा के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा 'मेरे लिए, मेरे दादा भगवान के समान हैं। उनके लिए मेरे दिल में जो प्यार और सम्मान है, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता।'

राशा ने जाहिर किया उत्साह

राशा थडानी, जो इस फिल्म के साथ टॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं, उन्होंने तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने को लेकर अपना उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा, 'इस फिल्म के साथ तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू करके मुझे बेहद खुशी हो रही है। जय कृष्णा के साथ काम करना एक शानदार अनुभव रहा है। मैं इस फिल्म को दर्शकों के सामने पेश करने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं।'

ब्लास्ट में अब्राहम बने नजर आएंगे अर्जुन चिदंबरम, फैमिली एंटरटेनर फिल्म को लेकर बढ़ा उत्साह

फिल्म निर्देशक सुभाष के राज की आने वाली फिल्म ब्लास्ट लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर अब एक नई जानकारी सामने आई है, जिसने दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ा दिया है। मेकर्स ने खुलासा किया है कि अभिनेता अर्जुन चिदंबरम फिल्म में अब्राहम नाम का किरदार निभाते नजर आएंगे। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में अर्जुन सरजा, प्रीति मुखुनधन और अभिरामी दिखाई देंगे। अब अर्जुन चिदंबरम के किरदार की जानकारी सामने आने के बाद फैंस फिल्म की कहानी को लेकर और ज्यादा उत्साहित हैं। अभी उनके किरदार के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि फिल्म में उनकी भूमिका काफी अहम होने वाली है। फिल्म का निर्माण कर रही एजीएस एंटरटेनमेंट ने एक्स टाइमलाइन पर लिखा, ब्लास्ट की दुनिया में अब्राहम से मिलिए। इसके साथ फिल्म की रिलीज डेट और पूरी टीम को भी टैग किया गया। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है।

जानकारी के मुताबिक, ब्लास्ट 28 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। फिल्म को सेंसर बोर्ड से यू/ए सर्टिफिकेट मिल चुका है। मेकर्स का दावा है कि फिल्म में एक्शन, इमोशन और मनोरंजन का पूरा पैकेज देखने को मिलेगा, जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आएगा। यह फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखी जा सकती है।

फरवरी में मेकर्स ने घोषणा की थी कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। उस दौरान एजीएस एंटरटेनमेंट ने सोशल मीडिया पर एक खास वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें फिल्म के बीटीएस पल दिखाए गए थे। वीडियो में फिल्म की पूरी टीम शूटिंग खत्म होने की खुशी मनाती नजर आई थी। वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा था कि फिल्म अब पूरी तरह तैयार है और हमें बेसब्री से इंतजार है कि दर्शक इसे बड़े पर्दे पर देखें।

आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट बदली, जानें कब रिलीज होगी

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इन दिनों अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। आलिया 'अल्फा' और 'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी। अल्फा की रिलीज से पहले निर्माताओं ने इसकी नई रिलीज डेट जारी की है।

आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की आगामी स्पाई यूनिवर्स फिल्म 'अल्फा' की रिलीज डेट बदल दी गई है। जानें कब रिलीज होगी स्पाई यूनिवर्स की यह मूवी और क्या रही रिलीज डेट बदलने की खास वजह?

'अल्फा' की नई रिलीज डेट

आलिया भट्ट और शार्वरी वाघ की मुख्य भूमिका वाली एक्शन फिल्म 'अल्फा' अब अपने तय समय से एक हफ्ता पहले यानी 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पहले यह फिल्म 10 जुलाई को आने वाली थी। फैंस आलिया को एक्शन अवतार में देखने के लिए बेताब हैं। इस फिल्म से पहले आलिया ने फिल्म 'जिगरा' में एक्शन किया था।

क्यों बदली 'अल्फा' की रिलीज डेट

फिल्म 'धमाल 4' की रिलीज डेट 17 जुलाई तय होने के बाद, 'अल्फा' के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने यह फैसला लिया है। 3 जुलाई के आसपास कोई बड़ी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, इसलिए निर्माताओं को लगा कि फिल्म की कमाई के लिए यह सबसे सही समय है। यह फिल्म 'वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स' (YRF Spy Universe) का हिस्सा है और इसमें बॉबी देओल भी नजर आएंगे।

इस बदलाव से 'अल्फा' को बॉक्स ऑफिस पर बिना किसी मुकाबले के दो हफ्ते का पूरा समय मिल जाएगा। यह फिल्म दो कॉमेडी फिल्मों 'वेलकम टू द जंगल' (26 जून) और 'धमाल 4' (17 जुलाई) के बीच रिलीज हो रही है, जिससे अलग जॉनर (एक्शन) होने के कारण इसे फायदा मिल सकता है।

'लव एंड वॉर' में नजर आएंगी आलिया

मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की बड़े बजट की फिल्म 'लव एंड वॉर' है। यह फिल्म एक शानदार लव ट्रायंगल और युद्ध के माहौल पर आधारित होगी, जो 1964 की क्लासिक फिल्म 'संगम' से प्रेरित है। इस फिल्म में आलिया के अलावा रणबीर कपूर और विक्की कौशल मुख्य भूमिका में नजर आएंगे।

'ब्राउन' को लेकर करिश्मा कपूर का खुलासा, ठुकराया था रीटा ब्राउन का रोल

करिश्मा कपूर अपनी नई सीरीज 'ब्राउन' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। हाल ही में करिश्मा ने बताया कि उन्होंने इस सीरीज को पहले ठुकरा दिया था। जानिए फिर क्यों की यह सीरीज?

करिश्मा कपूर वेब सीरीज 'ब्राउन' में रीटा ब्राउन के किरदार में नजर आने वाली हैं। 5 जून को ओटीटी पर रिलीज होने वाली इस सीरीज को लेकर करिश्मा ने हाल ही में कई खुलासे किए हैं। पहले करिश्मा ने इस रोल के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वह रीटा ब्राउन बनकर ओटीटी पर तलहका मचाने के लिए तैयार हैं।

क्यों किया था सीरीज के लिए मना?

बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर जल्द ही एक नई सस्पेंस थ्रिलर सीरीज 'ब्राउन' में नजर आने वाली हैं। यह सीरीज 5 जून को ZEE5 पर रिलीज होगी। हाल ही में इसका ट्रेलर सामने आया था। एएनआई से बातचीत के दौरान करिश्मा ने बताया कि जब शुरुआत में उन्हें यह रोल मिला, तो उन्होंने मना कर दिया था। दरअसल, करिश्मा ने सोचा था कि वह इतने दिनों के लिए कोलकाता जाकर 'ब्राउन' की शूटिंग कैसे करेंगी। लेकिन जब वह डायरेक्टर अभिनय देव से मिलीं और अपने किरदार को गहराई से समझा, तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया।

रीटा ब्राउन के रोल में नजर आएंगी करिश्मा

करिश्मा कपूर अपनी नई वेब सीरीज 'ब्राउन' में रीटा ब्राउन के किरदार में नजर आएंगी। करिश्मा इस शो में एक पुलिस अफसर का रोल कर रही हैं, जो शराब की आदी है और अपने पुराने दुखों से जूझ रही है। करिश्मा के मुताबिक, उनका किरदार अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन बाहर से बेहद मजबूत है। करिश्मा ने कहा, 'दर्शकों को इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा।'

अपने करियर पर बात करते हुए करिश्मा कपूर ने कहा कि उन्होंने बहुत कम उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। अब वह बहुत ज्यादा काम नहीं करना चाहतीं। वह सिर्फ वही प्रोजेक्ट्स चुनती हैं, जो सीधे उनके दिल को छूते हैं।

सीरीज 'ब्राउन' को लेकर स्टार कास्ट की राय

मशहूर एक्ट्रेस सोनी राजदान भी इस सीरीज में हैं। सीरीज को लेकर सोनी ने कहा कि मां-बेटी के रिश्तों को इस सीरीज में पुराने घिसे-पिटे तरीके से अलग, बिल्कुल नए अंदाज में दिखाया गया है।

अभिनेता जिस्सू सेनगुप्ता ने कहा कि इस सीरीज में डायलॉग्स से ज्यादा खामोशी के पलों की बहुत बड़ी भूमिका है।

सूर्य शर्मा इस सीरीज में 'अर्जुन सिन्हा' नाम के एक पुलिस वाले का रोल निभा रहे हैं, जो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है।

क्या है 'ब्राउन' की कहानी?

डायरेक्टर अभिनय देव ने बताया कि 'ब्राउन' एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है। इसकी कहानी कोलकाता शहर पर आधारित है। यह इंसानी भावनाओं, उनके डर, संघर्ष और कमियों को दिखाती है, जिससे आम लोग खुद को जोड़ पाएंगे। इस सीरीज को जी स्टूडियोज ने प्रोड्यूस किया है।

रानी चटर्जी ने शेयर किया लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी का बीटीएस वीडियो

भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री रानी चटर्जी इन दिनों अपनी फिल्म लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार को अभिनेत्री ने सोशल मीडिया पर फिल्म के धमाकेदार गाने यू. पी. वाली बिहार वाली का पर्दे के पीछे का वीडियो शेयर किया। इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में रानी के साथ उनकी सह-कलाकार संजना भी नजर आ रही हैं। दोनों अभिनेत्रियां गाने की धुन पर अच्छे से परफॉर्म करती दिख रही हैं। इसमें फिल्म के डायरेक्टर (निर्देशक) दोनों अभिनेत्रियों को गाने के स्टेप्स और उसके पीछे के भावों को गहराई से समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो पोस्ट कर अभिनेत्री ने फैंस से पूछते हुए लिखा, क्या आपने गाना सुना?

इस फिल्म में रानी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं जबकि संजना बिहार की रहने वाली हैं। यह कहानी एक ही घर में रहने वाली दो अलग-अलग राज्यों की बहू के बीच होने वाली छोटी-छोटी नोकझोंक और प्यार भरे झगड़ों पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ लखनऊ की शानोशौकत वाली यूपी की लड़की और दूसरी तरफ अपनी सादगी और परंपराओं को मानने वाली बिहार की लड़की के बीच मजेदार मुकाबले होते हैं।

लखनऊ की बड़की पटना की छोटकी के निर्देशक मंजुल ठाकुर हैं जबकि फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और मंजुल ठाकुर हैं। फिल्म की कहानी अरविंद तिवारी ने लिखी है। फिल्म में रानी चटर्जी और संजना सिंह के अलावा प्रशांत सिंह, अलोक सिंह, रीना रानी, ललित उपाध्याय, श्वेता वर्मा और प्रेम दुबे भी हैं। फिल्म का वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर 23 मई और 24 मई को बी4यू भोजपुरी चैनल पर हुआ था, जिसके बाद इसे दर्शकों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

हॉलीवुड स्टार से बेटी की तुलना पर महिमा चौधरी ने दी प्रतिक्रिया, यूजर्स ने पूछा - क्या उसने डेब्यू कर लिया?

कई सोशल मीडिया यूजर्स महिमा चौधरी की बेटी की तुलना अमेरिकी एक्ट्रेस से कर रहे हैं। इस पर महिमा चौधरी ने अपना रिएक्शन दिया है।

महिमा चौधरी अपनी बेटी को लेकर चर्चा में हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है, जिनमें उनकी बेटी एरियाना मुखर्जी की तुलना अमेरिकी एक्ट्रेस मिका अब्दुल्ला से की जा रही है।

कई फैंस तो 'ऑफ कैंपस' की स्टार मिका को एरियाना की हमशक्ल भी कह रहे हैं।

एरियाना से मिलती हैं मिका अब्दुल्ला

सोशल मीडिया पर एरियाना चौधरी और मिका अब्दुल्ला के बीच तुलना को लेकर खूब चर्चा है। मिका, प्राइम वीडियो की पॉपुलर सीरीज 'ऑफ कैंपस' में ऐली हेस का किरदार निभाती हैं। कई यूजर्स ने यह भी बताया कि मिका काफी हद तक महिमा चौधरी के जवानी के दिनों की तरह दिखती हैं।

एरियाना ने नहीं शुरू की एक्टिंग

इस वायरल ट्रेंड पर हंसते हुए महिमा ने बताया कि उनके दोस्त, परिवार और फैंस लगातार उन्हें इस हॉलीवुड एक्टर के क्लिप और स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। महिमा चौधरी ने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'हां, मुझे पता है। मुझे वह (एरियाना) बहुत पसंद है, वह कमाल की है। दो अलग-अलग महाद्वीपों के लोगों में इतनी जबरदस्त समानता कैसे हो सकती है? यह समानता इतनी ज्यादा चर्चा का विषय बन गई कि कुछ लोगों को तो यह भी लगने लगा कि एरियाना ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया है। मैंने उन्हें बताया कि उनसे अभी एक्टिंग नहीं शुरू की है।'

तुलना पर खुश होती हैं महिमा

महिमा ने कहा कि उन्हें ये तुलनाएं प्यारी लगती हैं। उन्होंने कहा 'किसी इतने प्यारे इंसान को देखना और यह सुनना कि आप दोनों एक जैसे दिखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं इस समानता से बहुत उत्साहित हूं क्योंकि मुझे वह बहुत प्यारी लगती है। अगर लोग कहते हैं कि मैं उसके जैसी दिखती हूं या एरियाना उसके जैसी दिखती है, तो मैं बहुत खुश होती हूं।

क्या करती हैं एरियाना?

2007 में जन्मी एरियाना, अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी और अपनी मां के साथ पब्लिक अपीयरेंस की वजह से काफी मशहूर हो गई हैं। हालांकि उनकी अभी डेब्यू की कोई योजना नहीं है। उन्होंने अभी-अभी 12वीं पास की है। महिमा के मुताबिक उनकी बेटी आखिरकार एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में करियर चुनती है, तो उन्हें बहुत खुशी होगी।

खास खबर

सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ सुरक्षा कवच बनी एचपीवी वैक्सीन

रायपुर। किशोरी बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य में एचपीवी (ह्यूमन पेपिलोमावायरस) टीकाकरण अभियान को व्यापक रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार के निर्देशानुसार 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क एचपीवी वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य बालिकाओं को भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे से बचाते हुए उनके स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की नींव को मजबूत करना है। बलरामपुर जिले में कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी के मार्गदर्शन में अभियान प्रभावी रूप से संचालित हो रहा है। जिले में अब तक 2084 किशोरी बालिकाओं को एचपीवी वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामरी में 150 के लक्ष्य के विरुद्ध 142 बालिकाओं का टीकाकरण किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के चिन्हांकित स्वास्थ्य संस्थानों में टीकाकरण का कार्य निरंतर जारी है। कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने अभिभावकों एवं किशोरियों से इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य पहल का लाभ उठाने की अपील करते हुए कहा कि एचपीवी वैक्सीन गर्भाशय ग्रीवा (सर्वाइकल) कैंसर की रोकथाम में अत्यंत प्रभावी और पूरी तरह सुरक्षित है।

वनांचल शिक्षा सेवा न्यास छत्तीसगढ़ का 10 दिवसीय नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग प्रारंभ

कोरबा। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा के प्रचार-प्रसार एवं संस्कारयुक्त शिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वनांचल शिक्षा सेवा न्यास छत्तीसगढ़ द्वारा आयोजित 10 दिवसीय नवीन आचार्य प्रशिक्षण वर्ग-2026 का शुभारंभ 2 जून की सायंकाल से कोरबा में प्रारंभ। यह प्रशिक्षण वर्ग 13 जून प्रातः तक संचालित होगा, जिसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आचार्य सहभागी बनेंगे। इस प्रशिक्षण वर्ग का भव्य उद्घाटन समारोह 3 जून 2026, बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर सीएसईबी (पूर्व), कोरबा में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन को सफल बनाने के लिए वनांचल शिक्षा सेवा न्यास के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लगातार जुटे हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोरबा नगर पालिक निगम की महापौर संजू देवी राजपूत उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कोरबा चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन करेंगे। वहीं नमामि हसदेव सेवा समिति, कोरबा के संरक्षक श्रेष्ठ सिंह ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

कटकोना शिविर में गूंजा नशामुक्ति का संदेश

एमसीबी। सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत विकासखंड खडगवां के ग्राम कटकोना में आयोजित जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर केवल समस्याओं के समाधान का मंच नहीं बना, बल्कि सामाजिक जागरूकता और जनकल्याण का भी प्रभावी केंद्र साबित हुआ। समाज कल्याण विभाग की सक्रिय भागीदारी से शिविर में नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और दिव्यांगजन सशक्तिकरण के संदेश ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। शिविर में समाज कल्याण विभाग द्वारा आयोजित जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान रूप से नशामुक्त समाज निर्माण का संकल्प लिया। लोगों ने जीवन में किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने तथा अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करने की शपथ ग्रहण की।

हर गांव तक पहुंचेगी विकास की रोशनी- वित्त मंत्री चौधरी

वित्त मंत्री ने 32.15 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास, ग्रामीण अधोसंरचना, खेल एवं जनसुविधाओं को मिलेगी नई गति

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी ने अपने जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर पुसौर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिडमिडा, त्रिभौना, तुरंगा, कोतासुरा एवं कोड़ातराई का दौरा कर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास, भूमिपूजन एवं लोकार्पण करते हुए क्षेत्र के विकास को नई दिशा देने का संकल्प दोहराया।

ग्रामीणों को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि प्रदेश और रायगढ़ की जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसे विकास कार्यों के माध्यम से सार्थक करना उनका दायित्व है। उन्होंने कहा कि रायगढ़ जिले का समग्र एवं संतुलित विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और प्रत्येक गांव तक विकास की रोशनी पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास, सुशासन और जनकल्याण के नए युग की ओर अग्रसर है। प्रदेश सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना है। गांव, गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है, जिससे गांव और शहर के बीच विकास का अंतर कम हो सके। उन्होंने कहा कि आज जिन कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया है, वे केवल निर्माण कार्य नहीं, बल्कि क्षेत्र के हजारों लोगों के बेहतर भविष्य की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कें किसी भी क्षेत्र की प्रगति का आधार होती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी, विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज जाने में आसानी होगी तथा स्थानीय व्यापार और रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। वहीं मिनी स्टेडियम जैसे निर्माण कार्य ग्रामीण युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे।

वित्त मंत्री चौधरी ने 26 करोड़ 80 लाख रुपये से अधिक लागत के चार महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इनमेंकृ त्रिभौना-कोड़पाली पहुंच मार्ग पर 2.80 करोड़ रुपये की लागत से 1.50 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मिडमिडा हाईस्कूल पहुंच मार्ग पर 1.24 करोड़ रुपये की लागत से 0.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य। मचिदा-कलमी मार्ग पर 3.04 करोड़ रुपये की लागत से 3.50 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य। कोड़ातराई- पुसौर-सूरजगढ़ मार्ग पर 19.71 करोड़ रुपये की लागत से 6.70 किलोमीटर सीसी सड़क निर्माण कार्य।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच और बेहतर बनेगी। 5.35 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण वित्त मंत्री चौधरी ने 5 करोड़ 34 लाख 82 हजार रुपये की लागत से पूर्ण हुए विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया।

इनमें लोक निर्माण विभाग द्वारा 3 करोड़ 92 लाख 39 हजार रुपये की लागत से निर्मित गोतमा-कोतासुरा मार्ग (3.50 किलोमीटर) प्रमुख रूप से शामिल है। इसके अलावा जिला खनिज न्यास निधि से 65 लाख रुपये की लागत से निर्मित तुरंगा मिनी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया।

साथ ही जनपद पंचायत पुसौर क्षेत्र के ग्राम मिडमिडा, कोड़ातराई, त्रिभौना एवं तुरंगा में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण, मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन मद, विधायक निधि एवं मुख्यमंत्री घोषणा के तहत निर्मित सीसी रोड, सांस्कृतिक शेड, महतारी सदन, यात्री प्रतीक्षालय एवं अन्य जनसुविधा संबंधी कार्यों का भी लोकार्पण किया गया।

बंदूक छोड़ थामा वॉलीबॉल सुकमा के पुनर्वास केंद्र में गूंजा भारत माता की जय का नारा

मुख्यधारा में लौटे 113 युवाओं के जीवन में आया नया सवेरा, 5जी कनेक्टिविटी और खेलों से संवर रहा भविष्य

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। नक्सलवाद के दंश को पीछे छोड़ छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला अब बदलाव की एक नई और बेहद खूबसूरत इबारत लिख रहा है। जिला प्रशासन द्वारा संचालित जिला पुनर्वास केंद्र में रह रहे 113 आत्मसमर्पित युवाओं (42 महिलाएं और 71 पुरुष) के जीवन में वास्तव में नया सवेरा आ चुका है। कभी जंगलों में भटकने और हाथों में घातक हथियार थामने वाले ये युवा अब न सिर्फ समाज की मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं, बल्कि पुनर्वास केंद्र के परिसर में पहली बार इनके द्वारा लगाए गए भारत माता की जय के नारे सुकमा के बदलते और सुरक्षित होते भविष्य की गवाही दे रहे हैं।

पुनर्वास केंद्र में इन युवाओं की दिनचर्या अब पूरी तरह अनुशासित, सुरक्षित और रचनात्मक हो चुकी है। सुबह उठकर बागवानी (गार्डनिंग) और साफ-सफाई करने के बाद सभी युवा मिल-जुलकर नाश्ता और भोजन तैयार करते हैं। प्रशासन ने इनके बौद्धिक विकास के लिए दो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की है, जो इन्हें प्रतिदिन सुबह-शाम अक्षर ज्ञान, बुनियादी गणित और अंग्रेजी सिखाते हैं। समाज का वैध और सम्मानित हिस्सा बनाने के लिए प्रशासन कलेक्ट्रेट के सिंगल विंडो रूम के माध्यम से इन सभी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, श्रम कार्ड और वोटर आईडी जैसे महत्वपूर्ण शासकीय दस्तावेज प्राथमिकता से बनाया जा रहा है। इसके साथ ही इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल प्रशिक्षण (स्किल ट्रेनिंग) भी दी जा रही है।

प्रशासन की इस मानवीय पहल का सबसे खूबसूरत रंग खेल और मनोरंजन के मैदान में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा के अनुरूप, जब इन पूर्व नक्सलियों से उनके मनोरंजन और खेल की पसंद पूछी गई, तो सबसे ज्यादा रुझान वॉलीबॉल के प्रति दिखा। इसके बाद प्रशासन ने केंद्र में खेल प्रतियोगिता की शुरुआत की, जिसमें युवक-युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कभी अत्याधुनिक हथियार संभालने वाले इन हाथों में जब वॉलीबॉल आई, तो मैदान पर उनकी खेल प्रतिभा और किक देखकर हर कोई हैरान रह गया। ओयाम जोगा, वेको हुंगा और सोड़ी सोमड़ी जैसे युवा अब खेल के मैदान में अपना जौहर दिखाकर बेहद खुश और उत्साहित हैं। दिनभर की रचनात्मक गतिविधियों और खेल के बाद शाम को सभी युवा संगीत कक्ष में सुर-ताल मिलाते हैं, जिससे उनका भरपूर मनोरंजन होता है। वर्तमान डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जिला प्रशासन ने इन युवाओं को 5त्र स्मार्टफोन भी उपलब्ध कराए हैं। इस आधुनिक तकनीक के जरिए देश-दुनिया की खबरों से कटे रहने वाले ये युवा अब समकालीन समाज और नई जानकारियों से सीधे जुड़ पा रहे हैं।

सीएम हेल्पलाइन (1076) के नोडल अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। सुशासन एवं अभिसरण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में सीएम हेल्पलाइन (1076) के विभागीय नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण में शासन के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सुशासन एवं अभिसरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन आम नागरिकों तक सुशासन पहुँचाने का सबसे सशक्त और सुलभ माध्यम है। उन्होंने सभी नोडल अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आम जनता की शिकायतों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। अधिकारियों को आधुनिक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ळतपमअंदबम त्मकतमेंस लेजमउ) के व्यावहारिक उपयोग की जानकारी दी गई। शिकायतों का समय पर निराकरण न होने की स्थिति में उन्हें प्रक्रिया, एल-1 से एल-4 स्तर तक स्वचालित रूप से ट्रांसफर करने की तकनीकी प्रक्रिया समझाई गई। नागरिकों से उनकी संतुष्टि का फीडबैक लेने की पारदर्शी प्रक्रिया के बारे में बताया गया। सुशासन एवं अभिसरण विभाग के संयुक्त सचिव मयंक अग्रवाल ने बताया कि इस सिस्टम से शिकायत निवारण दर और नागरिक संतुष्टि दोनों में तेजी से सुधार आएगा। आगामी लॉन्चिंग के बाद नागरिक टोल-फ्री नंबर 1076 पर कॉल करके, वेब पोर्टल, समर्पित मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायतें सीधे दर्ज करा सकेंगे।

परंपरा और तकनीक का संगम : किसान भरत बने प्रगतिशील खेती की मिसाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बिलासपुर जिले के मोपका ग्राम के किसान भरत क्षेत्रपाल उन प्रगतिशील किसानों में गिने जाते हैं, जिन्होंने अपने अनुभव, नवाचार और मेहनत के बल पर खेती को लाभकारी एवं टिकाऊ व्यवसाय का स्वरूप दिया है। लगभग 30 से 35 वर्षों के कृषि अनुभव के साथ उन्होंने अपनी 23 एकड़ भूमि को विविधतापूर्ण और आधुनिक कृषि का सफल मॉडल बना दिया है।

खेती के प्रति समर्पण और दूरदर्शिता ने उन्हें क्षेत्र के किसानों के बीच एक अलग पहचान दिलाई है। वर्षों से खेती करते हुए उन्होंने विभिन्न फसलों के उत्पादन में दक्षता हासिल की है। अरबी (जिमीकंद) और हल्दी उनकी प्रमुख फसलें हैं, जिनकी खेती में उन्हें विशेष सफलता मिली है। इन फसलों के साथ उन्होंने केले की उन्नत खेती को भी अपनाया और उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए।

वर्तमान में श्री क्षेत्रपाल अपनी 8 एकड़ भूमि पर जी-9 किस्म के केले की खेती कर रहे हैं। उनके खेत में केले की दूसरी फसल सफलतापूर्वक तैयार हो रही है, जो उनकी वैज्ञानिक खेती और बेहतर प्रबंधन क्षमता का प्रमाण है। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की उनकी सोच ने उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि की है। श्री क्षेत्रपाल अपने खेतों में ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करते हैं। इस तकनीक से पानी की बचत होने के साथ-साथ फसलों को आवश्यकतानुसार नमी प्राप्त होती है। इससे उत्पादन लागत में कमी आती है और फसल की गुणवत्ता बेहतर होती है। जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी यह तकनीक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्नत खेती में क्षेत्रपाल की उपलब्धियों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई है। वर्ष 2006 और 2011 में भारत सरकार द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित कृषिरत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ये सम्मान उनकी लगन, नवाचार और कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान का प्रतीक है।

अब सड़कों से सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं बच्चे

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सड़क जैसी परिस्थितियों में जीवन यापन कर रहे बच्चों को सुरक्षित बचपन, शिक्षा और सम्मानजनक जीवन से जोड़ने के लिए 01 जून से 30 जून तक राज्यव्यापी विशेष सघन अभियान चलाया जा रहा है। बाल सक्षम नीति-2022 के तहत सड़क पर रहने वाले, भिक्षावृत्ति, बाल श्रम एवं अपशिष्ट संग्रहण में संलग्न बच्चों की पहचान कर उनका रेस्क्यू और पुनर्वास किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार बच्चों को सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टरों के नेतृत्व में गठित विशेष रेस्क्यू टीमों द्वारा चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अभियान चलाकर बच्चों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। रेस्क्यू किए गए बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर उनकी आवश्यकतानुसार संस्थागत देखभाल, पारिवारिक पुनर्स्थापन एवं अन्य पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

साथ ही बच्चों और उनके परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं वित्तीय सहायता से भी जोड़ा जा रहा है।

राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क जैसी परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का पुनर्वास केवल एक माह का अभियान नहीं, बल्कि सतत प्रक्रिया है।

80774 ग्रामीण परिवारों को मिला अपना पक्का आशियाना

कवर्धा। कबीरधाम ज़िले में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से हजारों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सुख, समृद्धि और सम्मान का संचार हो रहा है। यह तब होता है जब योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन एवं प्रबंधन से समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान सहज उपलब्ध हो और जीवन की गाड़ी अच्छे से आगे बढ़ती रहे। ग्रामीण हितग्राही अपना खुद का घर बनाकर उसमें रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और जीवन की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। गरीब ग्रामीण परिवारों को उनका अपना पक्का घर मिले इस सोच के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा प्रयास अब साकार होने लगे हैं।

CAR DECOR
House Of Exclusive Seat Cover, Car Stereos Matting & Sun Control Film & Other Accessories
Shop No.3 Nafish Tower. Opp. Indian Coffee House, Akashganga, Bhilai
Mo.9300771925, 0788-4030919
K. Satyanarayan

पिलखा जलाशय बना महिला सशक्तिकरण की मिसाल

मुस्कान समूह की महिलाओं ने बोटिंग से बदली अपनी तकदीर

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ (या अन्य स्थानीय राज्यों) के विभिन्न हिस्सों में महिलाओं ने जलाशयों/तालाबों के प्रबंधन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों का सफल संचालन कर महिला सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल पेश की है। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं जल स्रोतों से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

सूरजपुर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन क्षेत्र पहाड़गांव स्थित पिलखा डैम से निर्मित सुंदर जलाशय आज न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र है, बल्कि महिला सशक्तिकरण की एक प्रेरणादायक मिसाल भी बन चुका है। यहाँ मुस्कान महिला स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने बोटिंग गतिविधि की शुरुआत कर आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखी है। समूह की अध्यक्ष श्रीमती सुनीता सिंह एवं सचिव श्रीमती यशोदा दास के नेतृत्व में इस 10 सदस्यीय समूह ने स्थानीय पर्यटन से जुड़कर स्वरोजगार का एक शानदार अवसर तैयार किया है। जलाशय का लुत्फ उठाने आने वाले पर्यटकों के लिए यहाँ बोटिंग सुविधा शुरू की गई है, जिसकी टिकट दर 50 रुपये प्रति व्यक्ति निर्धारित है। शुरुआती दौर में इन ग्रामीण महिलाओं के सामने संसाधनों की कमी, तकनीकी ज्ञान का अभाव और संचालन संबंधी कई बड़ी चुनौतियां थीं। इसके बावजूद, समूह की एकजुटता, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने इन बाधाओं को अवसरों में बदल दिया। महिलाओं ने किसी बाहरी मदद पर निर्भर रहने के बजाय, बोटिंग का संचालन, पर्यटकों की सुरक्षा और पूरे परिसर का प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं संभालते हुए अपने इस कार्य को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है।

इस सराहनीय पहल के माध्यम से समूह अब तक 74 हजार रुपये की शुद्ध आय अर्जित कर चुका है। इससे न केवल समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आज ये महिलाएं न केवल अपने परिवार के भरण-पोषण में हाथ बंटा रही हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।

मुस्कान महिला स्व-सहायता समूह की यह गौरवशाली उपलब्धि स्पष्ट करती है कि यदि ग्रामीण महिलाओं को सही अवसर, उचित सहयोग और एक मंच मिले, तो वे किसी भी क्षेत्र में सफलता का नया अध्याय लिख सकती हैं।

ॐ SAIRAM
Mobile Accessories
मोबाईल शॉप में कार्य करने हेतु लड़को की आवश्यकता है
7000415602
Shop No. 78, Himalaya Complex, Supela, Bhilai

ROCKEY INDUSTRIES
FURNITURE PALACE
Deals in: (Steel & Wooden) Luxury & Imported Furniture
Akash Ganga, Supela, Bhilai Ph. 2296430

चौरसिया ज्वेलर्स
आकर्षक सोने चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता
बेन्टेक्स एवं ग्रहरत्न उपलब्ध यहां
उचित ब्याज दर पर गिरवी रखी जाती है
मुक्तिधाम रोड, रामनगर, सुपेला, भिलाई
9827938211, 9827171332

Jaquar Roca Parryware AJAY FLOWLINE
Shri Vijay Enterprises
Sanitarywares, Tiles, CPVC Pipes & Bathroom Fittings etc.
Supela Market, Bhilai
PH. 0788-4030909, 2295573

खास खबर

दो ट्रेलरों की टक्कर के बाद लगी आग, चालक जिंदा जला

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मंगलवार शाम दो ट्रेलरों की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। इस घटना में एक चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक ने वाहन से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचा ली। मामला तमनार थाना क्षेत्र का है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत झिकाबहाल के पास मंगलवार रात करीब आठ बजे दो ट्रेलरों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। हादसे में एक चालक ट्रेलर में फंस गया, जिससे उसकी जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं, दूसरे वाहन के चालक ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेलरों में कोयला लोड था। घटना की सूचना मिलते ही तमनार पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई तथा आग बुझाने के प्रयास में जुट गई।

क्रिकेट सट्टेबाजी के जाल में फंसकर युवक ने गंवाई जान

रायपुर। राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र स्थित इंद्रप्रस्थ फेस-2 के सी ब्लॉक की नौवीं मंजिल के पास युवक का शव मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना मिलते ही डीडी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि युवक ऑनलाइन आईपीएल सट्टेबाजी में शामिल था। शुरुआत में उसे कुछ आर्थिक लाभ हुआ था, लेकिन बाद में लगातार नुकसान का सामना करना पड़ा। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार, युवक पर आर्थिक दबाव बढ़ गया था और वह तनाव में चल रहा था। हालांकि, पुलिस ने अभी तक मौत के कारणों को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। घटना के बाद पुलिस ने बिल्डिंग और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। साथ ही परिजनों, परिचितों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर युवक की गतिविधियों और मानसिक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डीडी नगर थाना पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तकनीकी जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि युवक किन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से सट्टेबाजी में शामिल था और क्या इस मामले में किसी संगठित नेटवर्क की भूमिका है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऑनलाइन सट्टेबाजी युवाओं के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। मामले की जांच जारी है और सभी तथ्यों के सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

3.7 किलो गांजा के साथ महिला गिरफ्तार

रायपुर। नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन निश्चय के तहत तिल्दा नेवरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को अवैध गांजा रखने और बिक्री करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से लाखों रुपये मूल्य का गांजा, गोगो कोन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया है। पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि तिल्दा स्थित पटवारी कार्यालय के पास चाय-नाश्ते का ठेला संचालित करने वाली एक महिला अपने ठेले में अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री कर रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी,तलाशी के दौरान महिला के पास रखे एक थैले से 3 किलो 737 ग्राम गांजा, 33 नग गोगो कोन तथा एक बैटरी चालित इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद किया गया। जब्त सामग्री की कुल कीमत करीब 1 लाख 73 हजार 700 रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार महिला की पहचान भारती बगवानी (37 वर्ष) निवासी सिंधी कैंप, तिल्दा नेवरा के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

तीन प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर 48 लाख ठगे, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट का दिया झांसा

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर मोटा मुनाफा दिलाने का लालच देकर लोगों से 48 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को शेयर ट्रेडिंग का जानकार बताकर निवेशकों को हर महीने 3 प्रतिशत तक रिटर्न देने का भरोसा देता था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफदो अलग-अलग मामले दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी टोमन दास साहू, हनुमान मंदिर के पास पुरानी बस्ती सुपेला का निवासी है। उसके खिलाफ शेयर मार्केट में निवेश कराने के नाम पर धोखाधड़ी की कई शिकायतें मिली थीं। शिकायतों की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।

आरोपी के घर और कार्यालय की तलाशी के दौरान पुलिस ने एक कार, एक लैपटॉप, एक सीपीयू, एक की-बोर्ड, दो मॉनिटर, 10 चेक बुक, दो मोबाइल फोन, लेन-देन से संबंधित चार डायरी और 10 ट्रॉफियां जब्त की हैं। जब्त दस्तावेजों और बैंक रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

हालांकि, पुलिस के अनुसार 10 से अधिक अन्य पीड़ितों के सामने आने की जानकारी है। ऐसे में जांच आगे बढ़ने पर ठगी की कुल राशि 48 लाख रुपए से अधिक हो सकती है।

रिटायर्ड कर्मचारी से 10 लाख की ठगी

पहले मामले में सेक्टर-6 भिलाई निवासी पीपी. राव (63) ने शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि वे शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। मोहल्ले के एक परिचित ने उनकी मुलाकात टोमन दास साहू से कराई थी।

आरोपी ने खुद को शेयर ट्रेडिंग का विशेषज्ञ बताते हुए कहा कि निवेश करने पर हर महीने 3 प्रतिशत तक मुनाफा मिलेगा और मूलधन पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उसकी बातों पर भरोसा कर पीपी राव ने 18 दिसंबर 2024 को उसे 10 लाख रुपए नकद निवेश के लिए दिए थे।

शुरुआती 6 महीने तक आरोपी ने तय रकम के अनुसार लाभांश का भुगतान किया, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया। इसके बाद उसने भुगतान बंद कर दिया। जब पीपी राव ने अपनी मूल रकम वापस मांगी, तो आरोपी ने अलग-अलग बैंकों के कई चेक दिए। हालांकि खातों में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण सभी चेक बाउंस हो गए।

सरकारी कर्मचारी और उसके साथी से 38 लाख की ठगी

दूसरे मामले में रायपुर निवासी दीपक गाडगे ने शिकायत दर्ज कराई है। वे मेकाहारा अस्पताल में स्टोर कीपर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके साथी भीष्म महिलांग पहले से ही टोमन दास साहू के यहां निवेश कर चुके थे। उन्हीं के माध्यम से उनकी मुलाकात आरोपी से हुई थी।

दीपक गाडगे के अनुसार, टोमन दास साहू ने उन्हें भी हर महीने 3 प्रतिशत तक मुनाफा देने और मूल रकम पूरी तरह सुरक्षित रहने का भरोसा दिलाया था। इस भरोसे पर उन्होंने अलग-अलग समय में अपनी मां के बैंक खाते और अन्य माध्यमों से कुल 23 लाख रुपए निवेश किए। वहीं उनके साथी भीष्म महिलांग ने भी करीब 15 लाख रुपए लगाए थे। जब दोनों ने अपनी जमा पूंजी वापस मांगी, तो आरोपी ने 12 लाख रुपए का एक चेक दिया। हालांकि बैंक में प्रस्तुत करने पर वह चेक बाउंस हो गया।

शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निवेश की गई रकम वापस मांगने पर आरोपी लगातार बहाने बनाता था। कई बार उसका कार्यालय बंद मिलता था और वह जानबूझकर मिलने से बचता था। पीड़ितों के अनुसार आरोपी व्हाट्सएप कॉल पर गाली-गलौज करता था और उन्हें जान से मारने तथा गायब कर देने की धमकी भी देता था। जब भी वे अपनी रकम वापस लेने उसके पास पहुंचते, वह उनसे मिलने से कतराता था।

10 से ज्यादा पीड़ित आए सामने

आरोपी ने केवल इन शिकायतकर्ताओं ही नहीं, बल्कि कई अन्य लोगों से भी निवेश के नाम पर लाखों रुपए की रकम जुटाई है। मामले में अब तक 10 से अधिक पीड़ितों के सामने आने की जानकारी मिली है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी शुरुआत में निवेशकों को तय मुनाफा देकर उनका भरोसा जीतता था। इसके बाद वह उनसे बड़ी रकम निवेश करवाता था और कुछ समय बाद भुगतान बंद कर देता था। जांच अधिकारी फिलहाल आरोपी के बैंक खातों और वित्तीय लेन-देन की गहन पड़ताल कर रहे हैं।

टाउनशिप में एसी का आउटर चोरी करने वाले शातिर पकड़ाए, नाबालिग सहित तीन आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। बीएसपी टाउनशिप के सेक्टर 10 के घरों से हो रही चोरियों के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। भिलाई नगर पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में चोरी का सामान खरीदने वाला कबाड़ी भी शामिल है। कबाड़ी को आटो के साथ गिरफ्तार किया गया। दो आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया तथा नाबालिग को किशोर न्यायलय पेश किया गया ।

थाना भिलाई नगर क्षेत्र के सेक्टर-10 से लगातार छोटी-छोटी चोरियों की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस मामले में पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई थी। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर अंशुल व एक नाबालिग को पकड़ा गया। वहीं अमन साव को 2 नग एसी का आउटर ले जाते माल वाहक गाड़ी के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में अंशुल ने नाबालिग के साथ चोरी करना स्वीकार किया। वहीं चोरी का सामान अमन साव को बेचने की बात बताई। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल जुमला 3,65,000 एवं 49000 रुपए का माल जब्त किया। आरोपी अमन साहू द्वारा चोरी का माल खरीदे जाने से प्रकरण में धारा 305 (1) एवं 317 (2) प्रकरण में धारा 3 (5) जोड़ी गई।

बिलासपुर में डूबने से 2 युवकों की मौत

श्रीकंचनपथ न्यूज

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अलग-अलग जगहों पर हुए हादसों में 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। रतनपुर में एक युवक कमल ककड़ी (ढेस) निकालने के लिए तालाब में उतरा था, जहां कमल के बीच फंसकर गहरे पानी में डूब गया। वहीं, कोटा क्षेत्र के कोरी डेम में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की गहरे पानी में चले जाने से मौत हो गई। रतनपुर के करैहापारा निवासी कैलाश केंवट (43) कमल ककड़ी (ढेस) निकालकर बेचने का काम करता था और इसी से अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। रोज की तरह मंगलवार को वह रत्नेश्वर तालाब में ढेस निकालने गया था। इस दौरान वह तालाब के भीतर अधिक गहराई तक पहुंच गया और कमल के घने जाल में फंसने के कारण वह पानी में डूब गया। जब वह बाहर नहीं निकला तो आसपास मौजूद लोगों को अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी तलाश शुरू की। सूचना मिलते ही रतनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। घंटों तलाश के बाद देर शाम कैलाश केंवट का शव तालाब से बाहर निकाला गया।

वहीं, दूसरे हादसे में सरकंडा क्षेत्र के राजकिशोर नगर निवासी शोएब शेख अपने दोस्तों अफजल अहमद और जैनुल आबेदिन के साथ कोटा क्षेत्र स्थित कोरी डैम पहुंचा था। तीनों दोस्त नहाने के लिए डेम में उतरे थे। इसी दौरान शोएब गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। दोस्तों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ ही पलों में पानी में लापता हो गया।

काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने युवक का शव पानी से बाहर निकाला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

रेत और ईंट के अवैध परिवहन का मामला राजनांदगांव में एक माजदा व 3 ट्रैक्टर जब्त

श्रीकंचनपथ न्यूज

राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले में खनिजों के अवैध परिवहन के के मामले में खनिज विभाग ने एक माजदा वाहन और तीन ट्रैक्टर जब्त किया हैं। कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से ईंट और रेत का परिवहन करते पाए गए वाहनों को संबंधित थानों के सुपुर्द किया गया है। प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देश पर खनिज विभाग की टीम ने जिले के चांदो, बंशीबंजारी, खुज्जी, कुमरदा, साल्हे, छुरिया, बाबूटोला, चिचोला, तुमड़ीबोड़, सुकुलदैहान समेत विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक निरीक्षण अभियान चलाया। निरीक्षण के दौरान ग्राम टप्पा में मडियान निवासी घनश्याम वर्मा के स्वामित्व वाले माजदा वाहन क्रमांक सीजी 08 एल 3103 से अवैध रूप से ईंट परिवहन किया जा रहा था। वाहन को जब्त कर थाना तुमड़ीबोड़ के सुपुर्द किया गया।

इसी प्रकार ग्राम बाबूटोला क्षेत्र में तीन अलग-अलग ट्रैक्टरों से बिना वैध अनुमति रेत का परिवहन करते पाए जाने पर कार्रवाई की गई। जब्त किए गए ट्रैक्टरों में सोनालिका ट्रैक्टर के मालिक एवं चालक टेकराम पाल, ट्रैक्टर क्रमांक सीजी एआर 6853 के मालिक एवं चालक मनीष कुमार पाल तथा स्वराज ट्रैक्टर के मालिक एवं चालक रितेश सिन्हा शामिल हैं। सभी वाहनों को जब्त कर थाना चिचोला को सौंप दिया गया है। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए लगातार गश्त और निगरानी की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफआगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

रायपुर पुलिस का एक्शन, 154 अपराधी भेजे गए जेल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए एक सप्ताह के भीतर 154 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। मध्य जोन में चलाए गए इस अभियान के तहत फरार वारंटियों, आदतन अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

डीसीपी के नेतृत्व में चला विशेष अभियान

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश गुप्ता के निर्देशन में यह विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कमिश्नरेट को प्राप्त प्रतिबंधात्मक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए अपराधियों और असामाजिक तत्वों

के खिलाफ कार्रवाई की गई।

कार्रवाई के तहत 61 स्थायी और गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। वहीं, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से 93 संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ धारा 170 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

विशेष अभियान के दौरान अलग-अलग थाना क्षेत्रों में व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सबसे अधिक कार्रवाई गंज और तेलीबांधा थाना क्षेत्र में दर्ज की गई।

थाना-वार कार्रवाई की बात करें तो कोतवाली थाना क्षेत्र में 19, गोलबाजार में 18, मौदहापारा में 10, गंज में 36, सिविल लाइन में 25, तेलीबांधा में 34 और देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में 12 लोगों के खिलाफकार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे

डीसीपी बोले- अभियान रहेगा जारी

पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) उमेश गुप्ता ने कहा कि अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाया जा रहा यह विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि पुलिस ऐसे लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कर रही है, ताकि शहर में शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनी रहे। डीसीपी गुप्ता ने स्पष्ट किया कि अपराध और असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के प्रति किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।

शादी का झांसा देकर रेप, आरोपी गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

सक्ती। सक्ती में शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण करने और बाद में जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़िता से दोस्ती की थी। मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र का है।

पुलिस को दी गई शिकायत के अनुसार, पीड़िता की पहचान आरोपी अभिषेक केवट से साल 2024 में इंस्टाग्राम पर हुई थी। 22 दिसंबर 2024 को, जब पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे, तब आरोपी उसके घर आया। उसने शादी का वादा करते हुए पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए।

जबकि वह जानता था कि पीड़िता नाबालिग है। इसके बाद भी वह लगातार पीड़िता के घर जाकर उससे संबंध बनाता रहा। 28 मई 2026 को सुबह करीब 11 बजे, आरोपी पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर पोता सरसडोल रोड स्थित गोठान के पास ले गया।

वहां पीड़िता ने आरोपी से पूछा कि यदि उसे शादी नहीं करनी थी तो उसने शारीरिक संबंध क्यों बनाए। इस पर आरोपी ने पीड़िता का गला दबाकर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि वह उसे शादी के लिए मजबूर कर रही है। घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को पूरी जानकारी दी, जिसके बाद 1 जून 2026 को मालखरौदा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल केस दर्ज कर जांच शुरू की।

मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने आरोपी अभिषेक केवट (27) को उसके घर से घेराबंदी कर हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

कोरबा में अलग-अलग सड़क हादसे में 3 मौतें

खड़े ट्रक से टकराया वाहन, ट्रेलर-बाइक भिड़ंत, अज्ञात वाहन ने बाइक मारी टक्कर

श्रीकंचनपथ न्यूज

कोरबा। कोरबा में मंगलवार को तीन अलग-अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। पाली थाना पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है।

पहली घटना बिलासपुर-कटघोरा मुख्य मार्ग (एनएच 130) पर मुनगाडीह के पास हुई। तेज रफ्तार माल वाहक वाहन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि माल वाहक वाहन के चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन में सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। माल वाहक वाहन बिलासपुर की ओर से आ रहा था।

धौराभाटा में ट्रेलर-बाइक भिड़ंत

दूसरी दुर्घटना धौराभाटा के पास हुई। जहां ट्रेलर और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका इलाज पाली स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रेलर तेज रफ्तार में था और ओवरटेक करते समय बाइक उसकी चपेट में आ गई। हादसे के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया।

डूमरकछार ओवरब्रिज पर अज्ञात वाहन की टक्कर

तीसरी घटना डूमरकछार ओवर ब्रिज हाईवे पर हुई। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद वाहन चालक फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है।

चोरों ने उड़ाया 25 लीटर पेट्रोल, साथ में ड्राई फ्रूट्स

जगदलपुर। भानपुरी थाने से महज 50 मीटर की दूरी पर एक हैरान करने वाली चोरी का मामला सामने आया है। सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात करीब 1:52 बजे एक शातिर चोर ने तीन ठेला नुमा दुकानों के ताले तोड़े। चोर ने करीब 20 मिनट तक आराम से सामान खंगाला और 25 लीटर पेट्रोल से भरा जेरिकेन, सिगरेट व ड्राई फ्रूट्स लेकर फरार हो गया।

पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें चोर बिना किसी डर के बड़े आराम से सामान समेटता दिख रहा है। चोरी की इस वारदात की शिकायत पुलिस तक भी पहुंच गई और पुलिस अज्ञात चोर की तलाश में जुट गई है।

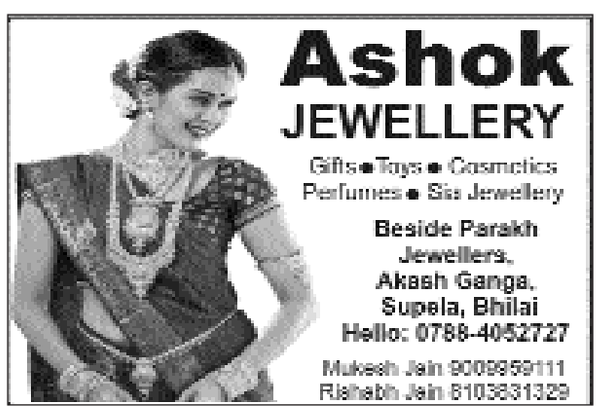

खास खबर

नैनो डीएपी और नैनो यूरिया ने बढ़ाई पैदावार, मृदा स्वास्थ्य को भी लाभ

कवर्धा। जिले के धरमपुरा गांव के किसान बालाराम साहू ने धान की खेती में नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग कर बेहतर उत्पादन मिला है। बालाराम ने बताया कि पिछले वर्ष शिविर में उन्हें नैनो डीएपी और नैनो यूरिया के उपयोग की जानकारी दी गई थी। उन्होंने अपने 6 एकड़ खेत में से 1 एकड़ में इन उत्पादों का प्रयोग किया। बीजोपचार के साथ फसल वृद्धि के दौरान नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया। उन्होंने बताया कि जिस खेत में नैनो उर्वरकों का उपयोग किया गया, वहां फसल का विकास बेहतर हुआ और उत्पादन भी अन्य खेतों की तुलना में 2 से 3 क्विंटल अधिक मिला। अच्छे परिणाम मिलने के बाद अब वे नियमित रूप से नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का उपयोग कर रहे हैं।

सहकारी समितियों में खाद का पर्याप्त भंडारण, 159 समितियों में उठाव

महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह द्वारा प्रतिदिन खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण एवं वितरण की समीक्षा की जा रही है। जिला विपणन अधिकारी के अनुसार जिले के 159 सहकारी समितियों में खाद का भंडारण किया गया है तथा किसानों की मांग के अनुरूप निरंतर वितरण किया जा रहा है। खरीफ 2026 के लिए जिले को 60 हजार 850 टन रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके विरुद्ध अब तक 16 हजार 294 टन से अधिक उर्वरकों का भंडारण किया जा चुका है, जो लक्ष्य का लगभग 26.78 प्रतिशत है। वहीं किसानों को अब तक 7 हजार 720 टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है। इनमें यूरिया 11 हजार 338 टन, डीएपी 1928 टन, एनपीके 449 टन एवं एसएसपी 1496 टन शामिल है। विभिन्न सहकारी समितियों में किसानों द्वारा खाद का उठाव किया जा रहा है। तोरेसिंहा सहकारी समिति बेलमुंडी अंतर्गत 108 किसानों को खाद का वितरण किया गया। गांव के किसान श्री कमलेश ने बताया कि उन्हें 8 बोरी यूरिया और 3 बोरी डीएपी प्राप्त हुआ। वहीं गांव के किसान शरद और गुलाल ने आसानी से डीएपी और यूरिया मिलने की बात कही।

पीएम मत्स्य संपदा : मछरी को कुछ भी हुआ तो एक्वा इंश्योरेंस करेगी नुकसान की भरपाई

- बीज संचयन के समय बीमा करवाने की अपील
- प्राकृतिक आपदा से लेकर रोग प्रकोप तक होगा कवर
- विकासखंड के मत्स्य अधिकारियों से करें सम्पर्क

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुर। जशपुर जिले के मत्स्य पालकों के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत संचालित एक्वा इंश्योरेंस योजना आर्थिक सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बन रही है। इस योजना के तहत मछली पालन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, आकस्मिक घटनाओं एवं मछलियों में फैलने वाली बीमारियों से होने वाले नुकसान की भरपाई की सुविधा उपलब्ध है।

मत्स्य विभाग ने जिले के सभी मत्स्य पालक किसानों से जुलाई-अगस्त माह में मत्स्य बीज संचयन के समय एक्वा इंश्योरेंस कराने की अपील की है। विभाग के अनुसार बीमा कवरेज मिलने से किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में किसानों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी तथा उनके मत्स्य व्यवसाय को सुरक्षा प्राप्त होगी।

योजना का उद्देश्य मत्स्य पालन को अधिक सुरक्षित और लाभकारी बनाना है, ताकि किसान जोखिमों की चिंता किए बिना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। एक्वा इंश्योरेंस से मत्स्य पालकों को प्राकृतिक आपदा अथवा रोग प्रकोप के कारण होने वाली क्षति की भरपाई प्राप्त हो सकेगी।

योजना से संबंधित अधिक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया के लिए मत्स्य पालक अपने विकासखंड के मत्स्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। विभाग द्वारा सभी विकासखंडों में आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बीमा का उद्देश्य मत्स्य किसानों को आकस्मिक घाटे से उबारकर व्यवसाय को स्थायित्व प्रदान करना है।

गृह निर्माण मंडल ने बनाया महत्वाकांक्षी प्लान

क्वींस क्लब ऑफ इंडिया का होगा उन्नयन बनेगा वर्ल्डक्लास हॉस्पिटैलिटी-वेलनेस केंद्र

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा राजधानी रायपुर स्थित क्वींस क्लब ऑफ इंडिया के विकास, संचालन एवं रख-रखाव के लिए लाइसेंस आधार पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत एजेंसी नियुक्त करने की महत्वपूर्ण परियोजना प्रस्तावित की गई है। यह पहल रायपुर को एक आधुनिक एवं प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी तथा वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगी।

परियोजना के तहत क्लब परिसर में स्क्वैश कोर्ट, टेनिस कोर्ट, जिम, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन हॉल, बिलियर्ड रूम तथा टेबल टेनिस हॉल जैसी आधुनिक खेल एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं विकसित एवं संचालित की जाएंगी। साथ ही वर्तमान अधोसंरचना का व्यापक आधुनिकीकरण एवं नवीनीकरण भी किया जाएगा।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि यह परियोजना रायपुर को एक नए प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी हब के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे राज्य में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा गुणवत्तापूर्ण शहरी अधोसंरचना विकास को नई गति प्राप्त होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्वींस क्लब ऑफ इंडिया की विशेष आवास योजना के अंतर्गत सांसद एवं विधायक वर्ग के 108 सदस्यों की विशेष सदस्यता पूर्ववत जारी रहेगी। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान वर्तमान सदस्यों के हितों एवं सुविधाओं का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव ने बताया कि परियोजना को लाइसेंस, डेवलप, ऑपरेट एवं ट्रांसफर मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित योजना के अनुसार क्लब की मौजूदा सुविधाओं का बेहतर संचालन एवं प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा तथा टेनिस कोर्ट क्षेत्र के रिक्त भूभाग पर लगभग 61 कमरों वाले आधुनिक आवासीय एवं हॉस्पिटैलिटी ब्लॉक का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परियोजना में लगभग 25 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। इससे अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास होने के साथ-साथ दीर्घकालिक राजस्व सृजन, आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। परियोजना की लाइसेंस अवधि 20 वर्ष निर्धारित है, जिसमें अतिरिक्त 10 वर्ष तक विस्तार का प्रावधान रहेगा।

श्री देव ने कहा कि शहर के प्रमुख क्षेत्रों से उत्कृष्ट सड़क संपर्क एवं बेहतर कनेक्टिविटी के कारण यह परियोजना निवेशकों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इसके माध्यम से राजधानी में उच्चस्तरीय आतिथ्य, खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का नया केंद्र विकसित होगा।

रायपुर में बनेगा जेम्स पार्क

मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम की सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर में अत्याधुनिक रायपुर जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क विकसित की जाएगी। नवा रायपुर में वर्ल्ड-क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। जो कॉर्पोरेट इवेंट्स, ग्लोबल बिजनेस मीट और प्रदर्शनियों के लिए उपयुक्त होगा, जिससे बिजनेस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।

बिलासपुर में ट्रांसपोर्ट नगर

बिलासपुर शहर में बढ़ते भारी वाहनों के दबाव और ट्रैफिक की समस्या को दूर करने के लिए एक विशाल सर्व-सुविधायुक्त ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ बड़े गोडाउन, लॉजिस्टिक्स हब, व्यापक पार्किंग स्पेस, वाहन रिपेयरिंग सेंटर और चालकों के लिए रेस्ट एरिया जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी।

अपने जन्मदिन पर मौसमी फल और मिठाइयों से तौले गए वित्तमंत्री चौधरी

श्रीकंचनपथ समाचार

रायगढ़। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के जन्मदिवस के अवसर पर रायगढ़ में क्षेत्रवासियों ने अनूठे अंदाज में उनका सम्मान किया। इस दौरान उन्हें मौसमी फलों एवं लड्डुओं से तौलकर शुभकामनाएं दी गईं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिक, समर्थक और शुभचिंतक उपस्थित रहे।

इस अवसर पर श्री चौधरी ने भावुक होते हुए कहा कि रायगढ़ क्षेत्रवासियों द्वारा उन्हें जन्मदिवस पर विभिन्न फलों एवं मिठाइयों से तौलना उनके जीवन के सबसे अनमोल क्षणों में से एक है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान क्षेत्रवासियों के स्नेह, प्रेम और उन पर किए गए अटूट विश्वास का प्रतीक है।

श्री चौधरी ने सभी नागरिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता का यह अपनापन और आशीर्वाद उन्हें जनसेवा के प्रति और अधिक समर्पण के साथ कार्य करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी शुभचिंतकों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों को जन्मदिवस पर मिली शुभकामनाओं और स्नेह के लिए धन्यवाद दिया।कार्यक्रम का माहौल उत्साह और उल्लास से भरा रहा तथा उपस्थित लोगों ने वित्त मंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की।

सुन्दरकांड पाठ में भी शामिल हुए वित्तमंत्री

श्री चौधरी अपने जन्मदिवस के अवसर पर रायगढ़ के महापल्ली में आयोजित सुंदरकांड पाठ में शामिल हुए। उन्होंने विधि-विधान से हनुमान जी की पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली, सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस के इस विशेष अवसर पर प्रभु श्रीराम एवं संकटमोचन हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने प्रदेश के विकास, जनकल्याण और सभी नागरिकों के सुखमय जीवन की प्रार्थना की।

बीजापुर-पुवर्ती मार्ग पर बने आधुनिक बेली ब्रिज का मुख्यमंत्री साय ने किया लोकार्पण

श्रीकंचनपथ समाचार

बीजापुर। जहां कभी दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियां विकास की राह में चुनौती बनती थीं, वहां आज आधुनिक अधोसंरचना नए अवसरों के द्वार खोल रही है। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बीजापुर जिले के सुदूर वनांचल क्षेत्र स्थित ग्राम कोण्डापल्ली पहुंचकर बीजापुर-पूवर्ती मार्ग पर निर्मित बेली ब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने पुल की निर्माण तकनीक, उपयोगिता और क्षेत्र के विकास में उसकी भूमिका की जानकारी लेते हुए इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाएं केवल निर्माण कार्य नहीं हैं, बल्कि वे दूरस्थ क्षेत्रों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास की मुख्यधारा से जोड़ने वाले मजबूत माध्यम हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास की पहुंच समाज के अंतिम व्यक्ति तक हो।

भारतीय सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यह बेली ब्रिज बीजापुर-पूवर्ती सड़क परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बेली ब्रिज पारंपरिक पुलों की तुलना में अधिक किफायती, मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इनका निर्माण सामान्य पुलों की अपेक्षा लगभग पांच गुना कम लागत में किया जा सकता है तथा इन्हें मात्र एक माह के भीतर तैयार किया जा सकता है। दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए यह तकनीक अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है।

उल्लेखनीय है कि बीजापुर जिले में अब तक 21 बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा चुका है। इन पुलों के निर्माण से दूरस्थ गांवों तक आवागमन सुगम हुआ है तथा लोगों को आवागमन, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और आवश्यक सुविधाओं तक पहुंच में बड़ी राहत मिली है। इन संरचनाओं ने क्षेत्र में विकास और जनसेवाओं के विस्तार को नई गति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने श्रमिकों की मेहनत और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के श्रमिक और युवा ही विकास यात्रा के वास्तविक निर्माणकर्ता हैं। उन्होंने श्रमिकों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके अनुभव भी साझा किए।

शिविर में 20 दिन के शिशु का बना आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र

रायपुर। गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा स्थित असेंबली हॉल में आयोजित सुशासन शिविर में मात्र 20 दिन के शिशु रुद्र कुमार गुप्ता के लिए आय, निवास और अस्थायी जाति प्रमाण पत्र एक साथ जारी किए गए। बच्चे के पिता आश्रित कुमार गुप्ता ने अपने पुत्र के आवश्यक शासकीय दस्तावेज तैयार कराने के लिए सुशासन तिहार शिविर में आवेदन प्रस्तुत किया था। राजस्व विभाग ने सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को शीघ्रता से पूर्ण किया और निर्धारित समय-सीमा के भीतर तीनों महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र तैयार कर माता-पिता को सौंप दिए। आमतौर पर इन दस्तावेजों को बनवाने के लिए नागरिकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन सुशासन तिहार के चलते इस परिवार की चिंताएं एक ही स्थान पर दूर हो गईं। नवजात को प्रारंभिक अवस्था में ही दस्तावेज मिल जाने से भविष्य की राह आसान हो जाएगी।

जनता के विश्वास को और मजबूत बना रहा सुशासन तिहार

विकास की नई इबारत लिख रहा बिलासपुर : केंद्रीय राज्य मंत्री साहू

श्रीकंचनपथ समाचार

बिलासपुर। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव आज सुशासन तिहार के अंतर्गत पुत्रीबाई स्कूल सामुदायिक भवन में आयोजित जिला स्तरीय शहरी समाधान शिविर में शामिल हुए।

+इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन और विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। बिलासपुर के विकास के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिविर में कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही ही वास्तविक सुशासन है। सुशासन तिहार ने शासन के प्रति लोगों के विश्वास को और अधिक मजबूत किया है। न्यायधानी बिलासपुर को उसकी पहचान और गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए लगातार बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए जा रहे हैं।

कार्यक्रम में अतिथियों ने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के तहत 12 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से अरपा राम सेतु से शनिचरी रपटा तक सड़क, नाला एवं पिचिंग कार्य तथा 5 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत से कुंदन पैलेस से सहारे गली होते हुए बस स्टैंड तक आरसीसी बॉक्स निर्माण कार्य का भूमिपूजन किया। कुल 18 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक के लागत के इन विकास कार्यों से शहर की अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम में अतिथियों ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित भी किया।

मुख्य अतिथि तोखन साहू ने कहा कि सुशासन तिहार शासन और जनता के बीच विश्वास को और सशक्त बनाने का अभिनव अभियान है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। प्रदेश विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ताकि कोई भी पात्र हितग्राही शासन की योजनाओं से वंचित न रहे। श्री साहू ने कहा कि बिलासपुर आज तेजी से बदलती हुई न्यायधानी के रूप में उभर रहा है। फोरलेन सड़कों का निर्माण, एयरपोर्ट विस्तार की दिशा में हो रहे प्रयास तथा कोपरा जलाशय का रामसर साइट के रूप में चयन इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कार्य कर रही हैं। बिलासपुर के समग्र विकास के लिए आवश्यक हर सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अरुण साव ने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान और शासन के प्रति उसका बढ़ता विश्वास ही सुशासन तिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार ने शासन और आमजन के बीच संवाद का प्रभावी माध्यम तैयार किया है, जिससे लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता मिल रही है।

उन्होंने कहा कि न्यायधानी बिलासपुर को विकसित करने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। विगत दो वर्षों में जिले में 412 करोड़ 57 लाख रुपए से अधिक के विकास कार्य स्वीकृत और संचालित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकास की यह गति आगे भी जारी रहेगी और न्यायधानी को प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में शामिल किया जाएगा।

रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने की दिशा में सकारात्मक पहल

जैविक खेती, नील हरित शैवाल से बेहतर हुई मिट्टी की सेहत

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में टिकाऊ एवं पर्यावरण अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए किसान अब जैविक खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों को अपना रहे हैं। कृषि विभाग के मार्गदर्शन में प्रदेश के कई किसान मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने, उत्पादन लागत कम करने और दीर्घकालीन कृषि लाभ सुनिश्चित करने के लिए जैविक विकल्पों की ओर अग्रसर हैं।

नील हरित शैवाल (ब्लू-ग्रीन एल्गी) का उपयोग भी ऐसी ही एक प्रभावी तकनीक के रूप में उभर रहा है, जो मिट्टी में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन की पूर्ति कर उसकी उर्वरता बढ़ाने में सहायक है।

प्रदेश में कई प्रगतिशील किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर वैज्ञानिक खेती को अपनाते हुए जैविक उपायों का प्रयोग कर रहे हैं। सरगुजा जिले के किसान धनेश्वर प्रसाद ने भी कृषि विभाग के अधिकारियों के तकनीकी मार्गदर्शन से प्रेरित होकर अपनी खेती में नील हरित शैवाल आधारित जैविक पद्धति को अपनाया है।

मिट्टी परीक्षण में नाइट्रोजन की कमी पाए जाने के बाद उन्होंने अपने स्तर पर नील हरित शैवाल उत्पादन की पहल की, जिससे खेतों को प्राकृतिक पोषण उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

विशेषज्ञों के अनुसार नील हरित शैवाल धान आधारित कृषि क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने का एक प्रभावी जैविक माध्यम है। इसके उपयोग से मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ती है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है तथा भूमि की उत्पादक क्षमता लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इससे खेती अधिक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल बनती है।

जैविक खेती के बढ़ते प्रयोग से किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाली उपज प्राप्त होने के साथ-साथ मिट्टी के स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिल रहा है।

कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग और जैविक विकल्पों को अपनाने से कृषि लागत कम की जा सकती है तथा भूमि की उर्वरता को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है।

राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि एवं मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन के प्रति जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मिट्टी परीक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों से जोड़ा जा रहा है।

जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में किसानों की बढ़ती भागीदारी न केवल कृषि उत्पादन को स्थायी आधार प्रदान कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, खाद्य सुरक्षा और भावी पीढ़ियों के लिए स्वस्थ कृषि व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950